>

Title : Further discussion on the resolution regarding special economic development package for eastern districts of the state of Uttar Pradesh, moved by Rajkumari Ratna Singh on the 11th December, 2009 (Resolution withdrawn).

MR. CHAIRMAN: The House shall now take up further discussion on the following resolution moved by Rajkumari Ratna Singh on the 11th December, 2009 :

> "Considering the socio-economic backwardness of the eastern districts of the State of Uttar Pradesh, also known as the Poorvanchal region, this House urges upon the Government to take immediate steps to formulate and implement a special economic development package for the region on the lines of package announced for Bundelkhand region."

The next speaker is Shri Harsh Vardhan.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Shri Harsh Vardhan has informed that he has some work. Therefore he has not come. You can call the other Member.

MR. CHAIRMAN: Okay. Shri Ramkishun to speak.

श्ाळ **रामकिशुन (चन्दौली):** माननीय सभापति जी, आपने मुझे राजकुमारी रत्ना सिंह के 11 दिसम्बर, 2009 को पेश किये गये संकल्प पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी जिलों की आर्थिक स्थिति के विषय में इसमें चर्चा है। आज उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल इलाका है, जिसमें ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Order, please.

श्री रामकिशुन : उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और पिछड़ेपन के चलते आज वहां की जनसंख्या काफी गरीबी और पिछड़े रूप से विकसित हो रही है। उन क्षेत्रों में कोई औद्योगिक घराना नहीं है, ना ही कोई बड़ा उद्योग है, जहां वहां के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी और उनके विकास के लिए कोई कार्यक्रम दिया जा सके। हमारे पूर्वांचल में किसानों की हालत बहुत ही दयनीय और बदतर इसलिए है कि वहां नदियों में पानी है, सिंचाई के संसाधन हैं, सिंचाई के संसाधनों का जाल है, फिर भी उन संसाधनों का सुदृढ़ीकरण न होने से, संसाधनों का रख-रखाव ठीक प्रकार से न होने से वहां के किसान काफी गरीबी के दौर से गुजरते हैं। उनके खेतों तक हम पानी नहीं पहुंचा पाते हैं। वहां की शिक्षा का जो स्तर है, वहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय, पूर्वांचल विश्वविद्यालय और संस्कृत विश्वविद्यालय जरूर हैं, लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि उसके बावजूद भी उस क्षेत्र की इतनी बड़ी आबादी है कि उससे पूरे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता है। वहां के लाखों नौजवान, लाखों बेरोजगार युवक नौकरियों की तलाश में दूसरे प्रांतों में जाकर बसने और काम करने का काम रहे हैं। इसलिए इस संकल्प के माध्यम से, इस प्रस्ताव के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं सरकार से कहूंगा कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड को विकास करने के नाम पर केंद्रीय सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा पैकेज देने का काम करके वहां के किसानों, बेरोजगारों और वहां की गरीबी को दूर करने का, किसानों के सिंचाई के संसाधन को मजबूत करने का जो काम किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से हमारी केंद्रीय सरकार से मांग है और आपके माध्यम से मांग है कि उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जो पिछड़ा और गरीब इलाका है, जो बुनकरों से भरा-पटा हुआ है। आज वहां के बुनकरों की हालत भी बहुत दयनीय है। वे आत्महत्या के शिकार हो रहे हैं।

वे आर्थिक रूप से कमजोर हैं। बुनकरों ने जो लोन ले रखा है, जो उनके बिजली के बिल हैं, वे उनकी अदायगी करने में असमर्थ हैं। हमारी सरकार से मांग है कि वह ऐसे गरीब बुनकरों के लोन माफ करने की पहल करे और बुंदेलखंड की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक सहायता देने का काम करे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल खेती के रूप में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वहां की जमीन उपजाऊ है लेकिन चंदौली, बनारस धान और गेहूं का कटोरा कहा जाता है। गाजीपुर खेती के मायने में एक मजबूत क्षेत्र है, लेकिन पानी रहते हुए भी वहां का किसान एक-एक बूंद पानी के लिए तड़पता है। पूर्वांचल के लोगों के लिए बहुत बड़ी शारदा सहायक नहर से पानी जाता है। वह नहर जर्जर और क्षतिग्रस्त हो गई है। अगर उस नहर को मजबूत बना दिया जाए, पक्का बना दिया जाए तो जो पांच सौ किलोमीटर बहराइच से आगे से पानी आता है और जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़ तक नहीं पहुंच पाता, उस पानी को पहुंचाने का काम हो सकता है। उसी प्रकार नारायणपुर पम्प कैनाल जो एशिया का सबसे बड़ा पम्प कैनाल है, उसके 12 पम्प हैं, लेकिन पचास किलोमीटर दूरी तक उसका पानी नहीं पहुंच पाता। वह नहर जर्जर और क्षतिग्रस्त है। चंदौली के किसान बराबर जन-आंदोलन और सूखे जैसी घटनाओं से प्रभावित होते हैं। वहां के किसान पानी के सवाल पर बराबर धरना, प्रदर्शन और आन्दोलन करते हैं और सरकारें उन पर लाठियां और गोलियां चलाने का काम करती हैं। उसका सिर्फ एक ही हल है कि अगर भभौली और नारायणपुर पम्प कैनाल की मुख्य नहर को सौ, दो सौ करोड़ रुपये लगाकर पक्का बना दिया जाए तो पूर्वांचल का वह इलाका जिसे हम धान का कटोरा कहते हैं, वहां धान की पैदावार बढ़ सकती है और किसानों की माली हालत भी ठीक हो सकती है। आज पूर्वांचल के कई ऐसे जिले हैं जो नक्सलवादी गतिविधियों की तरफ प्रभावित हो रहे हैं। वहां के नौजवान आज हथियार उठा रहे हैं। उनके सामने एक ही समस्या है कि उनके पास रोजगार नहीं है। सामन्तवादी ताकतें उनके हकों को छीनकर बैठी हैं। जो उनके संसाधन हैं, उन पर पूंजीपतियों, बड़े लोगों का कब्जा है जिससे वे नौजवान आज नक्सलवादी गतिविधियों की तरफ बढ़ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब वहां के विकास के लिए पूर्व मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह जी ने बहुत सी योजनाएं कीं। लेकिन आज वे योजनाएं इसलिए बंद पड़ी हैं कि केन्द्र सरकार की कोई मदद नहीं है और राज्य सरकार उसे गंभीरता से नहीं ले रही है। मैं आपके

माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि करमनासा पैकेज जो करोड़ों रुपयों का बनाया गया था, जो बराबर ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, उसे केन्द्र सरकार स्वीकार करे और नक्सलवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए उन क्षेत्रों के विकास के लिए काम करे।

पूर्वांचल में एक बाण सागर परियोजना है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सोन नदी से मिर्जापुर, चंदौली और सासाराम के जिलों तक उस बाण सागर परियोजना का पानी जाएगा। वह परियोजना अधूरी पड़ी हुई है, उसे पूरा करने का काम होना चाहिए।

मैं गंगा प्रदूषण की बात करना चाहता हूं। पानी है लेकिन गंगा का पानी प्रदूषित हो गया है। बनारस उस पूर्वांचल की राजधानी है, दुनिया की धार्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक राजधानी है। वहां के आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए केन्द्र सरकार को मदद करनी चाहिए। मैं आज आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि जब तक पूर्वांचल का विकास नहीं होगा, तब तक उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। पूर्वांचल एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहां के लोगों की आर्थिक हालत खराब है, जहां के लोगों की इनकम के स्रोत कम हैं। बुंदेलखंड की तर्ज पर पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष आर्थिक पैकेज देकर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक वातावरण को अच्छा बनाने का काम करना चाहिए। नहीं तो देश के विकास में पूर्वांचल एक पिछड़ता हुआ इलाका, गरीब के रूप में पहचान बनाने वाला इलाका बनता जायेगा, जो देश और हम सबके लिए अभिशाप होगा। जहां लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग राजनैतिक फकीर पैदा हुए हों, जहां संत कबीर, बुद्ध और ऐसे महान् संत पैदा हुए, उस क्षेत्र की उपेक्षा लगातार होती जा रही है। वहां जो भी सरकारें रहीं, वे सरकारें पूर्वांचल के प्रति सौतेला व्यवहार कर रही हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : राम किशुन जी, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री रामकिशुन : मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि पूर्वांचल के साथ सौतेला व्यवहार बंद करे। आप बुन्देलखंड को विकसित कीजिए। इसमें हमारा कोई विवाद नहीं है। ...(व्यवधान) आप उसे पैकेज दें, आर्थिक विकास के लिए आगे बढ़ायें। उस उद्योगविहीन क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने का काम करें, यही मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का मौका दिया। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जनपद ऐसे हैं जो आज गुरबत, पिछड़ेपन, रिजिनल इम्बैलेंसेज के शिकार हैं। वहां आर्थिक विषमताएं हैं और गरीबी और अमीरी की खाई निरंतर बढ़ती जा रही है। मैं उसकी तरफ इस सदन का ध्यान गंभीरता से आकृष्ट करते हुए केन्द्र सरकार से इस बात के लिए मांग करूंगा कि कम से कम उसने एक पहल की कि अगर आज देश में कहीं भी योजनाओं के समग्र विकास से कोई क्षेत्र क्षेत्रीय असंतुलन का शिकार हो रहा है या रिजिनल इम्बैलेंसेज का शिकार हो रहा है, तो उसे एक विशेष पैकेज दिया जाये। जिस तरह से बुन्देलखंड को एक आर्थिक विशेष पैकेज केन्द्र सरकार ने दिया है, उसी तरह से हम पूर्वी उत्तर प्रदेश के केवल कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को रेखांकित करना चाहते हैं। जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश, आज जो सबसे ज्यादा, सर्वाधिक गरीबी, आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार है, उसे भी जब तक केन्द्र सरकार द्वारा कोई आर्थिक रूप से विशेष पैकेज नहीं दिया गया, तो निश्चित तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश न केवल उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्रीय असंतुलन है, बल्कि देश के किसी भी हिस्से की तुलना में वह पिछड़ता हुआ चला जायेगा।

आज उत्तर प्रदेश की जो आबादी है, उसकी 40 प्रतिशत आबादी केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जनपदों में है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार का जो एक एनुअल प्लान बनता है या प्लेन प्लान आउटले है, उस बजट में 40 प्रतिशत हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए नहीं है। आज किसी भी क्षेत्र के विकास का क्या पैमाना होगा? उस क्षेत्र के विकास का पैमाना कृषि क्षेत्र में हो सकता है कि कृषि का उत्पाद क्या हो या उस क्षेत्र में कैश क्रॉप क्या है? उस कैश क्रॉप से किसानों की स्थिति क्या है या उद्योग से पैमान हो सकता है। इन्हीं चीजों से केवल किसी क्षेत्र के विकास का पैमाना हो सकता है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि वहां कैश क्रॉप गन्ना थी। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में निरंतर जो चीनी मिलें थीं, वे एक-एक करके बंद हो गयीं हैं। राज्य चीनी निगम की जितनी चीनी मिलें थीं, पिछले दिनों राज्य सरकार ने फैसला किया कि हम इन चीनी मिलों को बंद करेंगे और इसे हम निजी क्षेत्रों में बेचेंगे। पिछले कई वर्षों से इस बात का फैसला लिया गया, लेकिन अभी तक उन चीनी मिलों के रिवाइवल के लिए कोई काम नहीं हुआ। जब कांग्रेस सरकार थी, तो उस समय शुगर डेवलपमैंट फंड से हर साल हम दो चीनी मिलों को रिवाइव करते थे। हम इस बात का, 18 करोड़ की आबादी में, 40 प्रतिशत जिस क्षेत्र की यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी हो, मैं कहता हूं कि अगर राज्य सरकार न भी सपोर्ट करे, केन्द्र सरकार न भी सपोर्ट करे, लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट डिपाजिट रेशियो में एक पहल की थी कि अगर किसी इलाके में बैंकों में पैसा वहां की जनता और किसानों द्वारा जमा किया जायेगा, उस पैसे में जमा के अनुपात में कम से कम 60 प्रतिशत ऋण वहीं के लिए दिया जायेगा चाहे वह क्रॉप लोन के रूप में दिया जायेगा या उद्योग के लिए दिया जाये। लेकिन आज उस आरबीआई की जो एक आर. बी. बाज समिति की सिफारिश भी है, उस सिफारिश में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2002 तक हम 60 परसेंट सीडी रेशियो एचीव कर लेंगे।

आज देश में जहां कई राज्य ऐसे हैं जिनमें सीडी रेशियो 100 प्रतिशत से ऊपर जा रहा है, उत्तर प्रदेश का सीडी रेशियो 42 प्रतिशत है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का सीडी रेशियो मात्र 22 प्रतिशत है। अगर हम 100 रूपया जमा करते हैं, तो उसका 22 रूपए ही वहां विकास के लिए, वहां ऋण के रूप में वहां के लोगों को दिया जा रहा है और बाकी पैसा कहीं न कहीं मुंबई में बैंकों के मुख्यालयों से दूसरे क्षेत्रों में भेजा जा रहा है। उस समिति ने जो सिफारिश की थी, दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद से जो सरकारें बनीं, न उनकी यह प्राथमिकता थी कि राज्य का विकास कैसे होगा, न उनकी कोई कार्ययोजना था कि आरबीआई ने जो सिफारिश की है, उसके सापेक्ष हम उन बैंकों पर कोई दबाव डालें, जबकि आरबीआई ने कहा था कि एक कोर ग्रुप का गठन होना चाहिए। हमने कोर ग्रुप का गठन भी किया था और उस कोर ग्रुप के तहत राज्य के सभी जनपदों की तहसीलों में एक टास्कफोर्स का गठन एसडीएम की अध्यक्षता में किया गया था। किसी बैंक में कोई व्यक्ति, कोई किसान, कोई मजदूर, कोई नौजवान, कोई बेरोजगार अगर लोन के लिए एप्लीकेशन देगा तो हर महीने एसडीएम उसको मॉनीटर करेगा कि बैंकों ने उस लोन डिमाण्ड के अगेंस्ट कितना लोन मंजूर किया है। लेकिन आज वे सारी प्राथमिकताएं बंद हो गयी हैं। माननीय विजय बहादुर सिंह जी यहां बैठे हैं, अब इनकी प्राथमिकता केवल पार्क, स्मारक, मूर्तियां रह गयी हैं, इनकी प्राथमिकता यह नहीं रह गयी है कि राज्य के उन बेरोजगारों के, जिनके चेहरों पर भविष्य की आकांक्षाएं हैं, उनकी मदद की जाए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : The interruptions will not go on record. Please allow the hon. Member to speak.

*(Interruptions) â€¦**

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय सदस्य मेरे साथ विधानसभा में भी रहे हैं और ये जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार के समय पूंजी निवेश एवं उद्योग के कितने लेटर ऑफ इंटेन्ट इश्यू हुए। यह विषय ऐसा है, दो विद्वान व्यक्ति यहां बैठे हैं जो सरकार से संबंधित हैं। वे बताएं वहां पिछले तीन वर्षों में औद्योगिक विकास के लिए कितना पैसा निवेश हुआ या कोई बड़ा उद्योग वहां आया या कोई लेटर ऑफ इंटेन्ट जारी हुआ। आखिर किसी राज्य का औद्योगिक विकास हुए बिना कैसे बेरोजगारी दूर कर सकते हैं? आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवान बीए-एमए करने के बाद मुंबई की सड़कों पर, कुर्ला, अंधेरी, साकानाकी में मेहनत और मशक्कत करके अपने परिवार को जब मनीऑर्डर भेजता है, तो मनीऑर्डर इकोनोमी से उत्तर प्रदेश के घरों की परवरिश होती है। हमारे राज्य में आज उद्योग नहीं रह गए हैं, हमारे लोगों के हाथों में काम नहीं है। आज मनीऑर्डर इकोनोमी चल रही है। या तो कोई फौज में है या पीएसी में है, वहां से मनीऑर्डर से पैसा भेजते हैं, तो घर चलता है। आप हर महीने मुंबई इसलिए जाते हैं कि वहां आपके घरों के लोग हैं, आपके गांव और आपके क्षेत्र के लोग वहां हैं। आज हमारे 40 लाख लोग मुंबई शहर में हैं, गुजरात के सूरत, अहमदाबाद आदि शहरों में हैं। क्या यह बात उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर पेश नहीं करती है कि आज उत्तर प्रदेश में अगर रोजगार का अवसर होता, पूर्वी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के संबंध में राज्य की कोई योजना होती, राज्य का कोई ख्वाब होता, तो निश्चित तौर से आज वहां से लोगों का पलायन नहीं होता। आज यह वहां की नियति बन गयी है।

पिछले साल जब पूरा देश सूखे की चपेट में था, उस समय भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई थी क्योंकि हम नेपाल की फुटहिल्स में हैं। नेपाल की करनाली, जलकुण्डी, कोसी या अन्य किसी नदी में पानी ऊपर से आता है तो हम फुटहिल्स, तराई में होने के नाते उससे प्रभावित होते हैं, हमारे यहां तत्काल बाढ़ आ जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के 27 जिलों की यही नियति बन गयी है कि हर साल बाढ़ से या सूखे से फसलों की बर्बादी होती है। वहां किसान की मेहनत की कमाई की फसल बाढ़ और सूखे से खत्म हो जाती है। अगर कुछ फसल बची, तो आप लोग सहमत होंगे, आए दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसानों के खेतों में आग लग रही है, पूरा सिवान का सिवान जल जाता है। संत कबीर नगर से बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं, उनके इलाके में चार दिन लगातार किसानों के खेत जल गए। वहां का किसान महुली थाने पर गया, उन्होंने फायर ब्रिगेड मंगाने की मांग की, फायर ब्रिगेड नहीं आई। मुआवजे की मांग करने पर किसानों की छातियों पर गोली मारी गयी। पांच किसान आज भी जीवन-मौत से जूझ रहे हैं। अगर किसान के उत्पादन का नुकसान हो और उसे नेचुरल कैलामिटी में न रखा जाए, अगर किसान की फसल की बर्बादी होती है, तो कहा जाता है कि अगर खलिहान में आग लग जाए, लेकिन जब से कंबाइन आ गयी, अब कोई फसल खेत से खलिहान नहीं जाती है।

आज वह कम्बाइंड रूप से खेतों में ही गेहूं को अलग कर देती है, भूसे को अलग कर देती है और डंठल को अलग कर देती है। आज आवश्यकता है कि सम्बन्धित एक्ट में संशोधन किया जाए और खलिहानों की जगह खेत में भी आग लगे, तो उसे दैवीय आपदा मानकर किसानों को सहायता दी जानी चाहिए। लेकिन यह सब नहीं हो पा रहा है। हम लोगों ने इसी सदन में चर्चा की थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में हजारों बच्चे जैपनीज एनसाइफैलिटीज से मर जाते हैं। उस बीमारी का आज तक कारण नहीं पता चल पाया है कि मस्तिष्क ज्वर से जो लोग मरते हैं, उस बीमारी के वायरस क्या हैं। केवल प्रिवेंटिव हो सकता है, फिर भी इस बीमारी के बाद सारा जीवन विकलांग हो जाता है और वे अभिशप्त जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो जाते हैं। इस तरह वे अपने परिवार वालों पर बोझ बन जाते हैं। एक तरफ यह विडम्बना कि पहले से ही घर में गरीबी और गुरबत और दूसरी तरफ लाचार और अपंग बेटा। इससे आप समझ सकते हैं कि परिवार के मुखिया के सामने अंधेरा ही छाया रहता है। इस तरह उस बच्चे के मां-बाप उम्र से पहले ही उसकी परवरिश करने से टूट जाते हैं।

हम सब जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो उद्योग थे, वे बंद हो गए। गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाना था, वह बंद हो गया। बस्ती इंडस्ट्रियल इस्टेट बंद पड़ी है। आज सिद्धार्थ नगर जो हमारा जनपद है, वहां जीरो इंडस्ट्री है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जनपद हैं जो उद्योग शून्य हैं। आज वहां पर कोई उद्योग लगाने की बात नहीं होती। राज्य के परिव्यय में जो हमारा 40 प्रतिशत हिस्सा बनता है, वह भी हमें नहीं मिल रहा है। इन सब बातों को देखकर आप कैसे कहेंगे कि हम उत्तर प्रदेश का विकास करेंगे।

इसी लोक सभा में यूपीए की पिछली सरकार ने एक विधेयक पास किया था। उस विधेयक में प्रावधान था कि जैसे ब्राजील में एथोनोल बनाते हैं, उसी तरह यहां भी बनाया जाए। इसके लिए अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का उद्धार करना है, उन्हें रिवाइव करना है, जिससे किसानों की विपन्नता की स्थिति में गुणात्मक परिवर्तन हो, उनके जीवन की शैली को सुधारा जा सके, जिससे वे अपने परिवार के जीवनयापन की सम्भावनाएं बढ़ा सकें तो इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकार भी कम से कम वैसा ही विधेयक अपने यहां पास करे। पिछले दिनों वहां की सरकार ने इस तरह का विधेयक पास किया था कि हम गन्ने के रस से या शीरे से एथोनोल बनाएंगे। लेकिन जिस दिन इस विधेयक को राज्य की विधान सभा ने पारित किया कि हम एथोनोल बनाने का बिल पास करते हैं। अब चीनी मिलें इसे बना सकेंगी और वैकल्पिक ऊर्जा का उत्पादन कर सकेंगी, लेकिन उसी दिन यह भी फैसला किया गया कि हम राज्य चीनी निगम की सारी चीनी मिलों को बंद करेंगे। इस तरह के दोहरे मानदंड से कैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है।

सभापति महोदय : आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल : मान्यवर, मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं, केवल विषय पर ही अपनी बात कह रहा हूं।

आज वहां की पर केपिटा इनकम भी सबसे कम है। वर्ष 1993-1994 में आल इंडिया स्तर पर 7690 रुपए पर केपिटा इनकम थी, वहीं उत्तर प्रदेश की 5000 रुपए पर केपिटा इनकम थी। अगर आप वर्ष 2003-2004 की आल इंडिया स्तर पर पर केपिटा इनकम देखें तो वह डेढ़ गुना बढ़कर 11,799 रुपए हो गया, लेकिन उस समय भी उत्तर प्रदेश की पर केपिटा इनकम केवल 5702 रुपए ही थी। इसका मतलब यह है कि दस साल में केवल मात्र 500 रुपए के करीब ही उत्तर प्रदेश की पर केपिटा इनकम बढ़ी है। इससे आप सोच सकते हैं कि जहां आल इंडिया पर केपिटा इनकम 7000 रुपए से बढ़कर डबल हो गई, वहीं उत्तर प्रदेश में डेढ़ गुना नहीं, सिर्फ 500 रुपया ही बढ़ी है। यह बात सर्वविदित है कि ये आफिशियल पर केपिटा इनकम के आंकड़े हैं। इससे पता चलता है कि देश में प्रति व्यक्ति आमदनी दस सालों में दोगुनी हुई है, वहीं उत्तर प्रदेश में निरंतर घटती जा रही है, दस साल में मात्र 5066 रुपए से 5702 रुपए ही हुई है। इसका तात्पर्य है कि उत्तर प्रदेश के किसानों की, गरीब लोगों की पर केपिटा इनकम नहीं बढ़ रही है। सभापति जी, आप जानते हैं, आप विद्वान हैं कि पर केपिटा इनकम जो उत्तर प्रदेश की 5702 रुपए है, यह केवल किसान की नहीं है। इसमें वहां के उद्योगपतियों, डाक्टर्स, वकीलों, किसानों और बेरोजगारों का भी है। कोई भी पर केपिटा इनकम वार्षिक औसत से निकाली जाती है। आज साफ है कि सबसे ज्यादा देश में जिस राज्य में विषम परिस्थितियां हैं, तो वह उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र की हैं यानि पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं।

मैं समझता हूं कि यह वक्त का तकाजा है कि हमारी केंद्र की यूपीए सरकार क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। सड़क बनाने का

काम अभी तक केवल राज्य सरकारों का था। पीडब्ल्युडी हो या सड़क का मामला हो, ये राज्य के विषय हैं। आज हर गांव की कनेक्टीविटी हो। गांव की कनेक्टीविटी से गांव का विकास होगा और वे देश की मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे। किसानों का उत्पाद सीधा मंडियों में आएगा। बिचौलियों से किसानों को छुटकारा मिलेगा। अभी गेहूं के क्रय केंद्र नहीं खुले हैं। घोषणा हो गई है कि छह हजार क्रय केंद्र खुलेंगे। चालीस लाख मिट्रिक टन की खरीद उत्तर प्रदेश में होगी। अभी केवल एक लाख पन्द्रह हजार मिट्रिक टन की खरीद हुई है। अगर केंद्रीय पूल के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार खरीद नहीं कर रही है, कल विजय बहादुर जी गेहूं की मांग करेंगे और हमसे अपेक्षा करेंगे कि उनकी जो मांग हो, उसके अनुसार गेहूं और चावल भी दें। हम जरूरत देंगे, इसके बावजूद देंगे, लेकिन कम से कम जनहित की भी कुछ प्राथमिकताएं होनी चाहिए। प्रदेश की जनता की भी कुछ प्राथमिकताएं होनी चाहिए। साधु, संतों और महात्माओं के कार्यक्रमों को जरूर महिमा मंडित करें, बहन जी को महिमा मंडित करें, उनकी मूर्तियों को सम्मानित करें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हम इतना चाहते हैं कि प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखना चाहिए।...(व्यवधान) मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप अगर प्रदेश में सड़कें बन रही हैं, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बन रही हैं। राज्य के पास सड़कें बनाने के लिए पैसा नहीं है। हमने जिले की विजिलेंस एंड मोनिटरिंग समिति की बैठक की थी। हमने कहा कि बाढ़ से पूर्व बांध को रिपेयर करने के लिए गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ति, बलरामपुर आदि।

MR. CHAIRMAN : The time allotted for this discussion is exhausted. There are four more speakers and the hon. Minister has to reply. If the House agrees, we will extend the time of this Resolution by one hour.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The time for discussion on this Resolution is extended by one hour.

Shri Jagdambika Palji, you should conclude your speech in one minute.

SHRI ARJUN CHARAN SETHI (BHADRAK): The next Resolution is very important. We should have ample time so that that Resolution is taken up.

MR. CHAIRMAN: Yes.

श्री जगदम्बिका पाल : मैं आपका आभारी हूं कि सदन इस बात को गंभीरता से ले रहा है। चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों या प्रतिपक्ष के साथी हों, सभी को चिंता है। अभी कल वाले टांडा के पुल की बात हो रही है या इस तरह से जो बड़े पुल हैं। चाहे सीआरएफ हो, नेशनल हाइवेज़ हों या ग्रामीण सड़कें हों या नरेगा है, अगर आज कुछ पलायन रुका है, तो इनके कारण पलायन रुका है कि हम गांव के व्यक्ति को उसकी मांग के अनुरूप उसे काम का अवसर दे रहे हैं। अन्यथा उत्तर प्रदेश की स्थिति विषम हो जाती, भयावह हो जाती।

15.59 hrs. (Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair)*

मैं समझता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश फैजा, बाराबंकी से ही शुरू हो जाता है और देवरिया तक जाता है, जिसमें वाराणसी मंडल है, इलाहाबाद मंडल है, आजमगढ़ मंडल है, गोरखपुर मंडल है, देवीपाटन मंडल है, बस्ती मंडल है। इन 27 जनपदों में सबसे ज्यादा कुपोषण है। लोगों को जो 1400 या 1700 कैलरीज चाहिए, आज गांवों में लोगों को दो वक्त का भोजन नहीं मिलता है। यह हकीकत है। चाहे हम किसी पक्ष के संसद सदस्य हों, गांव की गरीबी देख कर हमें लगता है कि हम उस क्षेत्र के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आज उस क्षेत्र में बीमारियों से लोगों की मौतें हो रही हैं। उन जनपदों में मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए।...(व्यवधान) पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी बुंदेलखंड की तर्ज पर एक विशेष पैकेज की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता में आप हैं। आपकी जनता के प्रति जवाबदेही है। आप बताएं कि पिछले तीन वर्षों में आपने कौन सी विकास योजना लागू की है।

16.00 hrs.

कौन सी चीनी मिल चलाई? शुगर कॉरपोरेशन फेडरेशन के अंतर्गत प्राइवेट सैक्टर में कोई नई चीनी मिल स्थापित की हैं? ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: पाण्डे जी आप बैठ जाइए। आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

श्री जगदम्बिका पाल : आज बिजली की स्थिति यह है कि बिजली भी केंद्र में है और केंद्र से 80,000 करोड़ पैकेज भी दें तो सरकार किस लिए चलाएंगे? हम पैसा दें और ये मूर्ति लगाएंगे। हम केंद्र का पैसा अनुत्पादक चीजों में नहीं देंगे। हम केंद्र का पैसा प्रोडक्टिव, प्लान, डेवलपमेंट और विकास को देंगे इसलिए हमने तीन काम किया है। हमने रोजी और रोजगार के लिए नरेगा एक्ट बनाया। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा के लिए बनाया। राइट टू इन्फार्मेशन से लोगों को सूचना का अधिकार दिया। हमने इस देश में जनता को सबसे बड़ा अधिकार दिया है। चाहे रोटी का सवाल हो या सूचना का अधिकार हो। मैं कहना चाहता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश को आर्थिक रूप से विशेष पैकेज दिया जाए।

सभापति महोदय: श्री घनश्याम अनुरागी।

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): मैं इस सीट से अपनी बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप अपनी सीट पर नहीं है, इसके लिए आपको चेयर से परमिशन लेनी चाहिए।

श्री घनश्याम अनुरागी : सभापति महोदय, आपकी परमिशन हो तो मैं इस सीट से अपनी बात कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय: परमिशन है।

श्री घनश्याम अनुरागी (जालौन): माननीय सभापति महोदय, आज पूरे देश में गंभीर सूखे की स्थिति है क्योंकि पानी बहुत कम बरसा है। बुंदेलखंड व मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र में गंभीर संकट गहराते जा रहे हैं। वहां कृषि के अलावा दूसरा कोई जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। किसान पूरी तरह बर्बाद हो गया है, मजदूर बन गया है। मजदूर निश्चित तौर पर बड़े शहरों और नगरों में पलायन करने लगे हैं। किसान और मजदूर में कोई अंतर नहीं रह गया है। हमारे यहां गंभीर संकट है और इस समय पेयजल की कमी है और सिंचाई का कोई साधन नहीं है। वहां किसानों को पानी नहीं मिलता है, गहरे नलकूप नहीं हैं। बुंदेलखंड के पैकेज की घोषणा हुई है लेकिन एक रुपया भी वहां नहीं पहुंचा है। इस पैकेज में गहरे डीप बोर नहीं लिए गए हैं और नई पंप केनाल नहीं ली गई है। यह दुख का विषय है इसलिए किसानों के हित के लिए सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए इसलिए बुंदेलखंड के पैकेज में डीप बोर एवं पंप केनाल अनिवार्य रूप से लेना चाहिए। वहां लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि इसके लिए प्रत्येक जिले में 2000 इंडिया मार्क के हैंडपाइप पैकेज में लेना चाहिए। वहां सड़कें नहीं हैं जबकि गांव, मजरे और शहरों में जहां सड़कें नहीं है, वहां सड़कें बनवानी चाहिए और यह पैकेज में भी होना चाहिए। यहां बिजली आती नहीं है, दिल्ली में जाती नहीं है। यहां सड़कें बिछाने के लिए जगह नहीं है, जमीन के नीचे ट्रेन लाइन बिछाई जाती है लेकिन वहां जगह है और सड़कें नहीं बिछाई नहीं जाती हैं। हमारे यहां लोग भूख से तड़पकर मर जाते हैं और यहां बड़े लोगों के कुत्ते ब्रेड और मक्खन बर्बाद कर देते हैं जबकि हमारे यहां रोटी के अभाव में लोग भूख से तड़पकर मर जाते हैं। पानी के अभाव में मनुष्य और जानवर प्यास से तड़पकर मर जाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि वहां के किसानों और लोगों का भला हो इसका एक ही उपाय है कि तुंत सिंचाई लाभ योजना के अंतर्गत बुंदेलखंड को लीजिए। वहां गंभीर संकट है। जिस तरह से उड़ीसा मे कोराकुट, कालाहांडी और बालांगी में तुंत सिंचाई लाभ योजना लागू की गई है उसी तरह बुंदेलखंड में यह योजना लागू होना चाहिए तभी किसानों का हित होगा, लोगों का कल्याण होगा। वहां शिक्षा की भी दुर्दशा है। वहां गांव दूर-दूर हैं, मजरे हैं, डेरे हैं लेकिन स्कूल नहीं हैं। स्कूल हैं तो मास्टर नहीं हैं। बुंदेलखंड में स्कूलों और मास्टरों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करने की आवश्यकता है। इसी तरह भारी कमी अस्पतालों की है। अस्पतालों में न दवा है और न डॉक्टर है। वहां महिलाओं की बराबर की आबादी है लेकिन वहां महिला डॉक्टर और न विशेषज्ञ नहीं हैं। मेरी मांग है कि वहां अस्पताल में दवा उपलब्ध कराई जाए और शीघ्र डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए।

वहां पढ़ाई नहीं हो रही है। आज स्थिति बड़ी गंभीर है। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे केन्द्र की सरकार हो, पता नहीं, ये बुंदेलखंड के प्रति संवेदनशील नहीं है। आज बुंदेलखंड कराह रहा है, चिंघाड़ रहा है, वहां के लोग चिल्ला रहे हैं, वहां के लोग तड़प-तड़प कर भूख से मर जाते हैं। हमें यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि यदि वहां पेयजल के लिए ट्यूबवैल न दिये जा सकें तो कम से कम हैंड पम्प ही दे दिये जाएं। वहां पेयजल का संकट गहरा गया है। लोग कहते हैं कि बुंदेलखंड को पैकेज दे दिया गया। लेकिन बुंदेलखंड को अभी एक रुपया भी नहीं मिला है।

सभापति महोदय : ऑनरेबल मैम्बर, आपको तो स्पेशल पैकेज मिल गया है।

श्री घनश्याम अनुरागी : नहीं सर, बुंदेलखंड को अभी एक रूपया भी नहीं मिला है। ...(व्यवधान)

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.नारायणसामी): अभी यहां पूर्वांचल का सब्जैक्ट चल रहा है और आप बुंदेलखंड के बारे में भाषण दे रहे हैं। आप पूर्वांचल के विषय पर आइये। ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम अनुरागी : सर, मैं उसी प्रदेश का हूं। मैं कह रहा था कि वहां गहरे ट्यूबवैल्स की आवश्यकता है। आपने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को क्या पैकेज दिया है, केवल साढ़े सात हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं। जबकि वहां दो प्रदेशों में तीस हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसलिए हमारा निवेदन है कि बुंदेलखंड का पैकेज बढ़ाकर तीस हजार करोड़ रुपये किया जाए, जिसमें सिंचाई, शिक्षा, पढ़ाई, दवाई, किसानों की खाद, बीज मुक्त किये जाएं और वहां के लिए बिजली की अलग से व्यवस्था की जाए। मेरा कहना है कि बिजली के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को या तो धन दिया जाए या उत्तर प्रदेश सरकार को कहा जाए कि बुंदेलखंड को पर्याप्त बिजली दी जाए। वहां कुल दो घंटे बिजली दी जा रही है। वहां के लोग गर्मी से कराह रहे हैं। उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश की सरकार के विषय में तो हम क्या कहें, वह संवेदनशील नहीं है, वह संवेदनहीन सरकार है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि वहां सिंचाई, दवाई, पढ़ाई और सड़कों की गंभीर आवश्यकता है। इसलिए बुंदेलखंड के लिए एक बड़ा पैकेज बनाया जाए और सिंचाई के लिए व्यवस्था की जाए। वहां किसानों की गरीबी और भुखमरी को दूर करने के लिए व्यवस्था की जाए। इसके लिए मैं आपसे विशेष प्रार्थना करता हूं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि लोगों ने कहा कि बुंदेलखंड के पैकेज में जो योजनाएं बनाई गई हैं, वे नाकाफी हैं। वे ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। अधिकारियों द्वारा वहां के लिए ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं, जो केवल रुपया खाने के लिए बनाई गई हैं। उनसे वहां का विकास नहीं हो सकता है। ये नई योजनाएं हैं। मैं समझता हूं कि वहां के जनप्रतिनिधियों को बैठाकर योजनाएं बनाई जानी चाहिए। वे योजनाएं जिला योजना या जिला पंचायत में पास कराई जाएं या सांसद की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर जिले के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाए तथा उपयोगिता के अनुसार माननीय जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर योजनाएं बनाई जाएं और उन्हीं योजनाओं में बुंलेदखंड को आबंटित पैसा खर्च हो। वहां इन योजनाओं के लिए किसी से कुछ पूछा नहीं गया। अधिकारियों ने ए.सी. कमरों में बैठकर योजनाएं बना दी हैं। केवल इन योजनाओं में कितना ज्यादा कमीशन बचे, वहां के अधिकारी केवल खाने के चक्कर में और बुंदेलखंड पैकेज लूटने के चक्कर में वे ये सब कर रहे हैं। वहां केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार के अधिकारी मिलकर इस पूरे पैकेज को खाना चाहते हैं। वे लोग विकास नहीं करना चाहते हैं।

इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि गरीबों, किसानों और मजदूरों के प्रति संवेदनशील हो। इसके अलावा बुंदेलखंड से लगा हुआ पचास किलोमीटर का क्षेत्र है, चाहे इटावा हो, औरैया हो, चाहे कानपुर देहात तथा भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्र हो, घाटमपुर हो, इन इलाकों के लोग भी बुंदेलखंड के लोगों की तरह जीवनयापन कर रहे हैं। यहां भी वहीं परिस्थितियां हैं। इन सबको भी बुंदेलखंड की तरह पैकेज दिया जाए और उसी में कहा जाए कि वह भी बुंदेलखंड की परिस्थितियों जैसा है, वहां भी विकास के लिए योजनाएं दी जाएं अन्यथा उसी पैकेज में इन इलाकों को भी शामिल कर लिया जाए और जिस तरह से बुंदेलखंड के विकास के लिए पैकेज

दिया जा रहा है, उसी तरह इस क्षेत्र के विकास के लिए भी पैकेज की घोषणा की जाए।

मैं पुनः आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि केन्द्र सरकार इस पर विचार करे। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी केन्द्रीय योजनाओं के पूरे पैसे का दुरुपयोग कर रही है, इसलिए उसकी भी सीबीआई जांच कराई जाए। वहां 'नरेगा' योजना 'मरेगा' योजना हो गई है। इन योजनाओं में वहां कोई काम नहीं हो रहा है, केवल वसूली चल रही है तथा अधिकारी मिल-बांटकर नियम-कानून और गाइडलाइंस को ताक पर रखकर मनगढंत आंकड़े बनाकर पैसा लेने का काम कर रहे हैं।

इसलिए वहां की सरकार और अधिकारियों के खिलाफ भी सीबीआई जांच कराई जाए। जिस दिन वहां सीबीआई जांच कराई जायेगी, वहां की सरकार एवं अधिकारी कटघरे में खड़े होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

*SHRI PRASANTA KUMAR MAJUMDAR (BALURGHAT) : Sir, I am not against any special package for Bundelkhand but we should frame a specific policy. India is a big country with 619 districts. There are remote villagers, farflung areas where people cannot always reach. There has been selective development around the cities and towns. A proper policy should be there to decide which region is backward and which is not. Thus my proposal is a National Commission for Integration of Backward districts and Regions should be set up as soon as possible by the Central Government. The socio-economic picture of the country will be clear if we look at the report of this commission. If that is not done, then no development will be possible. The Government is saying that the Eastern India is less developed. You are aware that West Bengal can be divided into two parts – one part is North Bengal which is a backward region. Western Bihar, North Bihar and North Bengal lead to as far as Arunachal Pradesh. You will not see any irrigation facilities in the entire stretch. In India there are 5101 big dams for irrigation but in West Bengal we have only 28 dams. Arunachal Pradesh is the bordering state. But ironically the entire area lags behind on every account. If we want to have more progress, we have to take good care of the agricultural sector.

In order to develop agriculture, irrigation facilities must be improved. But there are major pressure groups which exercise their rights to be hill and have power to armtwist the administration. If political will is lacking, then we will never have any development in the underdeveloped areas, this has to be kept in mind. You know that the districts of Purulia, Bankura, Midnapore of West Bengal, are termed as 'Jangalmahal' area and these are Naxal-affected region. Who is going to bring about development in this area? The Government should include it within its policy

---

* English translation of the speech originally delivered in Bengali.

I hail from South Dinajpur. My specific proposal is to set up the commission and usher in development in right earnest. In North Bengal there is dearth of factories, enterprises or infrastructure. Colleges, technical educational institutions are also nowhere to be seen. In my Balurghat, not a single engineering medical or technical college is there. Transport facilities are also not up to the mark. Though Dalkhola is the gateway to Eastern India the roads are in very poor shape. Irrigation facilities are extremely inadequate. People are forced to drink arsenic contaminated water. In Tapan, and gangarampur block, potable drinking water is not available. Water is life. So something must be done in this regard. I wish the country progresses in the right direction. With these words I conclude my speech.

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, I will appreciate Rajkumari Ratna Singh as she has brought forward a most relevant resolution and without any ambiguity all the Members of this House should support the Resolution for the people of Eastern Uttar Pradesh.

The State of Uttar Pradesh is largely a collection of various geographical and historical regions which was carved out under the colonial administration. Later on, various regions have been segregated from Nawab of Oudh and the King of Garwal to form the United Province. Sir, in 1950, there were 51 districts in UP. With the creation of 15 more districts during the two regimes of Mayawati Government, the number shot up to 82. After 2000, when Uttaranchal has been constituted, UP is left with 70 districts. With the exclusion of Uttaranchal, the districts of UP could be categorised into six regions, namely, Rohilkhand, Bundelkhand, Upper Doab, Lower Doab, Eastern and Western UP. In so far as economic region is concerned, UP is categorised into four regions. And now, we are here deliberating on the situation of Eastern UP. It has been proposed by the Resolution that as the package of Bundelkhand has served some succour to the parched population of that rocky terrain, people of Eastern UP should be offered this kind of a package. This is the essence of the Resolution. Due to our young leader, Shri Rahul Gandhi, Bundelkhand had shot into prominence and by dint of his persistent endeavour, Bundelkhand has got the package.

Similarly, Eastern UP which is not only one of the most populated regions in our country but also one of the poorest areas of our country should be given the package like Bundelkhand. I support such a package.

If you see the parameters used to determine an area to be recognised as backward, then all the parameters will merge in Eastern UP. As far as population is concerned, Eastern UP consists of 40 per cent population of Uttar Pradesh. As far as density of population is concerned, Eastern UP has the high density of population in UP. It is 776 persons per square kilometre.

As far as urbanisation is concerned, it is one of the parameters which determines the backwardness of region. If you go by the index of human development, then urbanisation constitutes one of the indices. In terms of urbanisation, in the entire UP, highest percentage of urbanisation occurs in Western region. That is 28.25 per cent. But so far as Eastern UP is concerned, urbanisation has now been hovering around merely 11.78 per cent. That means out of 100 people in Eastern UP, only 11 people live in cities or towns. It clearly indicates that Eastern UP is a backward area not only in UP but also in the country as a whole.

So far as literacy is concerned, Eastern UP has a low literacy rate estimated at 54.27 per cent. In so far as foodgrain productivity is concerned, I must admit that foodgrain productivity in Bundelkhand region is the lowest among all the regions in UP. That is 11.56 quintal per hectare. For Western Uttar Pradesh, it is 25.19 quintal per hectare. The gross value of the agricultural output in Eastern Uttar Pradesh is merely Rs.16,000 to 18,000 per hectare.

As far as irrigation is concerned, Eastern Uttar Pradesh is regarded as a low irrigated area in Uttar Pradesh. The per capita power consumption is also one determinant to define an area as backward. In terms of per capita power consumption, it is the lowest in Eastern Uttar Pradesh, that is 118.80 kilo watt in the Eastern Uttar Pradesh, whereas the highest per capita power consumption is in Western Uttar Pradesh, that is 273.70 kilo watt.

Majority of the farmers in Eastern Uttar Pradesh are categorised as marginal farmers. 84.20 per cent of farmers in Eastern Uttar Pradesh are categorised as marginal farmers.

If you come to the industrial scenario of Eastern Uttar Pradesh, it is abysmal. The number of people in Eastern Uttar Pradesh who are engaged in registered factory is only 97 per lakh, whereas in Western Uttar Pradesh it is 645 per lakh. So, it is easy to assume that Eastern Uttar Pradesh is a backward region of Uttar Pradesh.

There is a place in Eastern Uttar Pradesh called, Chauri Chura, which has a historical significance. Mahatma Gandhi propagated and led the non-violent movement. At that time, people from Chauri Chura were leading a peaceful demonstration. When the demonstration was passing through a police station of that area, the local police pounced on them without any provocation. In retaliation, those peaceful demonstrators had thrown all the police personnel in the fire. It means that if we neglect a spark, in future it will engulf the entire edifice. Already Maoists are encroaching into the area by taking advantage of the poverty and the impoverishment of Eastern Uttar Pradesh.

However, Eastern Uttar Pradesh is a land which can be exploited to the benefit of the common people, which can be utilised to the benefit of the common people because it has fertile lands for agriculture. It has a huge tourism potential. It has Banaras. Buddhist places are there. A number of tourist places are there in Eastern Uttar Pradesh.

So, if a package could be given to Eastern Uttar Pradesh, I think it will do justice to the people of Eastern Uttar Pradesh. In this regard, I would request the Government to take immediate steps so that the content of the Resolution could be materialised.

With these words, I thank you and conclude my speech.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही): सभापति महोदय, आपने मुझे इस संकल्प पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। राजकुमारी रत्ना सिंह जी ने बुंदेलखंड की तर्ज पर जो मांग रखी है, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी विशेष पैकेज दिया जाए, उसके समर्थन में मैं कुछ बातें मांग के तौर पर, सलाह के तौर पर आपके सामने रखना चाहूंगा।

सभापति महोदय, इस देश को आजाद हुए लगभग 60 वर्ष हो चुके हैं और इतने वर्षों में सर्वाधिक शासन सत्ता अगर किसी एक दल ने संभाली है तो वह कांग्रेस पार्टी है। किसी भी क्षेत्र, प्रांत एवं जिले का विकास एक दिन में नहीं किया जा सकता, उसके लिए वर्षों का समय चाहिए, लेकिन आज भी हम पूर्वांचल के लोग पीछे हैं, पिछड़े हैं। हमारी प्रतिव्यक्ति आय एवं हमारे संसाधन कम हैं। हमारे लोग वहां दुखी, पीड़ित, भूखे एवं नंगे हैं, यह कोई राजनैतिक मुद्दा नहीं है। यह सोचने की बात है कि विकास में हम क्यों पीछे रह गए? हम पूर्वांचल के लोग क्यों आज भी दयनीय स्थिति में हैं। अगर इस पर सर्वाधिक जिम्मेदारी जाती है तो वह कांग्रेस पार्टी को जाती है, इन्होंने 45 वर्षों तक उस प्रदेश में शासन किया है। आज पाल साहब बोल रहे थे, वे कह रहे थे कि आपकी यह सरकार मूर्ति और पत्थरों में लगी है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि क्या इसके पहले सरकारों ने मूर्तियां नहीं लगवाई, पार्क नहीं बने? ...(व्यवधान) आप मेरी बात सुनिए।...(व्यवधान) आप सुनने का साहस कीजिए। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Shri Pandey, please address the Chair. Do not look to the other side. Please look at me. Please address the Chair.

â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बैठ जाइए।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : आप सुनने का साहस कीजिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Shri Jagdambika Pal, please sit down. Shri Goraknath Pandey, please address the Chair and speak on the economic development of the area. Do not blame this side or that side. In that way, we are to be blamed; everybody is to be blamed.

श्री गोरखनाथ पाण्डेय : यह बात आई थी, इन्होंने कहा था, इसलिए यह कहना जरूरी हो गया। ...(व्यवधान) ये बोल लेते हैं, लेकिन सुनने की क्षमता इनमें नहीं है, ये सुन नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने गलतियां की हैं। अपनी कालिख किसी दूसरे के चेहरे पर लगाना आसान है, लेकिन पहले ये सोचें कि इन्होंने 45 वर्षों में क्या किया?

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पाल साहब जिस क्षेत्र से आते हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि वहां एक नदी पर पुल बन रहा है, घाघरा नदी की बात अभी आई है। वहां दो पूर्ववर्ती सरकारों ने शिलान्यास किया। ...(व्यवधान) कांग्रेस ने भी किया और सपा ने भी किया। वहां पत्थर लगे और उसके बाद गायब हो गए। आज उसी घाघरा नदी पर सौ करोड़ की लागत से पुल बन रहा है, जिसके लिए इलाहाबाद और वहां की दूरी जो पांच घंटे की है, वह एक घंटे में होगी। उससे लोगों का समय भी बचेगा।...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बिजली की बात आती है। उत्तर प्रदेश बिजली उत्पादन करता है और उत्तर प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में बिजली केन्द्र द्वारा मंगा ली जाती है, जब कि पैदा हम करते हैं। अभी प्रदेशों की बात आई, पूर्वांचल में विद्युत का उत्पादन हो रहा है, लेकिन वही बिजली जब मध्य प्रदेश में जाती है या अन्य प्रदेशों में आती है तो उसी बिजली को फिर से उत्तर प्रदेश में जिस भाव से खरीदा जाता है,...(व्यवधान) आप पहले मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान) बेचने वाले ये लोग हैं और आरोप वर्तमान सरकार पर लगाते हैं। ...(व्यवधान)

मान्यवर मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि यह सुनने की कोशिश करें। ...(व्यवधान) बिजली की बात की जाती है, उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन हो रहा है। अनपरा, ओबरा, रेणुकूट, रिहंद, एनटीपीसी है, वहां से केंद्र बिजली दूसरे प्रदेश के लिए उसका शेयर मंगा लेती है और फिर वही बिजली उत्तर प्रदेश को ज्यादा दाम में सप्लाई की जा रही है। हमारे साथ दो तरह से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो वास्तविक स्थिति है, वह है प्राकृतिक प्रकोप। बाढ़ हर वर्ष आती है और हर वर्ष तबाह होते हैं गोरखपुर, बस्ती और आसपास के इलाके।

महोदय, हम जिस क्षेत्र से आते हैं, वह भदोही लोकसभा क्षेत्र है। भदोही जनपद है, जो बुनकरों से भरा हुआ है, जहां कालीन उद्योग है। केवल भदोही जनपद ही नहीं, भदोही जनपद से लगे हुए पूर्वांचल के कई सारे जनपद जहां हथकरघे चलते रहे, जहां कताई-बुनाई होती रही, जहां बहुत सारे ऐसे गरीब परिवार के लोग रहते हैं। वे गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करते हैं। उनकी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। वे आज गरीब नहीं हुए हैं। उनकी गरीबी चली आ रही है। उन्हें सल्तनत में गरीबी मिली है। अगर आज उसका सारा दायित्व वर्तमान सरकार को दे दिया जाए, तो यह नाइंसाफी है। ऐसा कहने वाले लोग अपने गिरेबान में झांके। ये थर्मल पावर की बात कहते हैं, उसको किसने बेचा है - वर्तमान सरकार ने या पूर्ववर्ती सरकारों ने? मनरेगा की बात कहकर ये अपनी पीठ थपथपाते हैं। आज पूरा सदन इस बात का

गवाह है कि इस मनरेगा से कितने लोगों का भला हो रहा है और उससे गांव के लोगों को क्या मिल रहा है?

महोदय, मैं आपके माध्यम से दो बिंदुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। जो हमारा क्षेत्र है, पूर्वांचल का भदोही लोकसभा क्षेत्र जहां से मैं चुनकर आता हूं, उससे सटे हुए बहुत सारे क्षेत्र हैं, जहां कालीन उद्योग से संबंधित लोग निवास करते हैं। वे भुखमरी की कगार पर हैं। सरकार उनके ऋण को माफ करे, उनको विशेष व्यवस्था दे और उनको विशेष पैकेज दे। ऐसे क्षेत्र जो नदियों से घिरे हैं, जो हर वर्ष कटान से पीड़ित हैं, उनकी हर वर्ष हजारों एकड़ जमीन समाप्त हो रही है। इसके संबंध में भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो क्षेत्र प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ की चपेट में आकर समाप्त हो रहे हैं, उन्हें भी सरकार को संरक्षण देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बुंदेलखंड की तर्ज पर पूर्वांचल के विकास के लिए अस्सी हजार करोड़ रूपए की मांग हमारी मुख्यमंत्री जी ने की है। अस्सी हजार करोड़ की मांग राज्य सरकार ने की है। यह केंद्र सरकार की ओर से की जानी चाहिए, ताकि पूर्वांचल का विकास हो सके।

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती): महोदय, आपने राजकुमारी रत्ना सिंह जी द्वारा 11 दिसंबर, 2009 को इस सर्वोच्च सदन में, उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी जिलों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग के संदर्भ में जो संकल्प रखा गया है, उस पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी ही नहीं अनुगृहीत भी हूं।

मान्यवर, राजकुमारी रत्ना सिंह जी के द्वारा रखे गए संकल्प को बल देते हुए, राजकुमारी रत्ना सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत संकल्प के आंकड़ों, माननीय श्री जगदंबिका पाल जी द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों और वक्तव्य तथा विशेष रूप से मैं आभारी होना चाहूंगा श्री अधीर रंजन चौधरी जी का, जिन्होंने पूर्वांचल की व्यथा को आंकड़ों में बहुत ही खूबसूरत ढंग से पिरोकर इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का कार्य किया है, जिससे इस संकल्प की आवश्यकता महसूस होती है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सर्वोच्च सदन से आग्रह करना चाहूंग और अपने आपको इन समस्त माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से सम्बद्ध करते हुए अपनी बात कहना चाहूंगा। चूंकि मैं जानता हूं, मैं भी पूर्वांचल का बेटा हूं और दर्द बहुत है बयां करने को, लेकिन सदन का समय बहुत ही कीमती है।

आपकी घंटी बजने लगे, इससे पहले मैं उन सभी आंकड़ों से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए अपनी बात पर आना चाहूंगा और इस सर्वोच्च सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से पास किया जाए। पूर्वांचल, जो अध-पिछड़ा हुआ है, अगर आजाद हिन्दुस्तान की बात की जाएगी और डैवलपमैंट इंडैक्स में सबसे पिछड़े हुए किसी क्षेत्र की बात आएगी तो वह पूर्वांचल के जनपदों की आती है। उसकी व्यथा कहने के लिए आप जितना भी समय देंगे, वह बहुत ही कम होगा। माननीय पाल साहब ने बहुत ही विस्तृत ढंग से बाढ़ की विभीषिका की बात की। बाढ़ से पूर्वांचल का क्षेत्र पचास प्रतिशत से भी अधिक प्रभावित होता है। हम शिवालिक बैल्ट, हिमालय की तराई में रहने वाले हैं। हमारा क्षेत्र तराई जनपद से है। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर...(व्यवधान) आप उसकी गाथा की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी आ रहा हूं। यदि सब कुछ व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो बाढ़ का जो पानी नेपाल से आता है, जिसकी विभीषिका हमारी दुर्दशा का कारण बन रही है, अगर हम उस जल का सदुपयोग करें तो निश्चित रुप से वह हमारे लिए वरदान साबित होगा।

अभी माननीय सदस्य ने बात की कि पूर्वांचल से कितने प्रधान मंत्री आए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब हम इस सर्वोच्च सदन में बैठते हैं, जब पूरे भारतवर्ष को विश्व के नक्शे पर प्रस्तुत किया जाता है, तब पूर्वांचल की बात और गौरव गाथा के बगैर हिन्दुस्तान की गौरव गाथा पूरी नहीं होती। 1857 के गदर से लीजिए। उससे पहले की व्यवस्था से लीजिए।...(व्यवधान) मंगल पांडे जी की बात कीजिए।...(व्यवधान)

शायद आज हमारे खून की जांच करानी पड़ जाएगी कि पांडे लोगों में ऐसे लोग कैसे आ गए। तिरंगे को सलाम करना भूल गए। उन्होंने निश्चित रूप से पूरे भारत के विकास की बात की। उन्होंने सेवा की भावना से अपनी कुर्बानी दी थी। पूर्वांचल की धरती सलाम करने योग्य है। शहीद अशफाकुल्ला, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अगर इन सबको शहादत दी गई तो पूर्वांचल के जिलों में दी गई और वहीं की माटी से इनके खून सने हुए हैं। वहां की माटी आज पूरे भारतवर्ष के लिए पूजनीय है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : There is a long list of speakers. Please try to confine to the subject.

SHRI B. MAHTAB (CUTTACK): He is probably the last speaker.

MR. CHAIRMAN: No.

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : मान्यवर, मैं सीधे सुझावों की ओर आ रहा हूं। कृपया बोलने का अवसर दीजिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: I can give you time but please be precise.

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : हमारे यहां बेरोजगारी है। हमारे यहां उर्वरा भूमि और श्रम शक्ति है जिसकी बदौलत पूरे हिन्दुस्तान में उत्पादकता बढ़ती है। अगर व्यवस्थित ढंग से कार्य किया जाए तो निश्चित रूप से वह वरदान साबित होगी।

मैं पूर्वांचल में बुद्ध पैकेज की बात करना चाहूंगा। पूर्वांचल के विशेष पैकेज में बुद्ध क्षेत्र, टूरिज़्म को जोड़ा जाए। अगर विश्व में कहूं, यदि डॉल्फिन्स का ब्रीडिंग सैंटर कहीं है तो वह पूर्वांचल में है। क्रोकोडाइल का ब्रीडिंग सैंटर वहीं है। श्रावस्ती, लुम्बनी, कुशीनगर, सारनाथ आदि बौद्ध तीर्थ स्थल वहीं हैं। जैनियों के तीर्थ स्थल वहीं हैं। इंटरनैशनल टूरिस्ट वहां आता है। वहां रिजर्व फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ में हम पूरे हिन्दुस्तान में सबसे रिच हैं। ट्राइब्स भी हमारे पास है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम इसे व्यवस्थित ढंग से करें। हमारी जो योजनाएं चल रही हैं, उनमें हम थोड़ा सा और परस्पर सामंजस्य बनाकर इसे अगर ढंग से व्यवस्थित कर दें, तो यह एक उद्योग ही नहीं, हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। हिन्दुस्तान को विदेशी विनिमय मुद्रा की आय का सबसे बड़ा स्रोत बनने का अवसर मिलेगा। ...(व्यवधान)

मान्यवर, बीआरजीएफ, बॉर्डर एरिया डेवलपमैंट, एमएचडीपी, एनआरएचएम, मनरेगा आदि को हम पूर्वांचल विकास निधि देते हैं। फेडरल सिस्टम में इम्प्लीमैंटेशन का काम स्टेट गवर्नमैंट का है। अभी मेरे माननीय भाई बोल रहे थे ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Do not go to that side; you please conclude.

...(*Interruptions*)

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय: मैं इतना बता देना चाहता हूं कि इन्होंने बिजली की बात की है। मान्यवर, अगर आज उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 20 वर्षों से कांग्रेस की सरकार नहीं रही। अगर इसकी जांच हम सही ढंग से करा लें कि उत्तर प्रदेश में पीक ऑवर्स में इन्होंने बिजली प्राइवेट सैक्टर से एनटीपीसी के अलावा कितनी खरीदी और क्यों खरीदी, उसकी दर क्या रही और फिर वह बिजली लेकर कहां गयी? उसे ग्रिड में डालने के बाद उसे क्या उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से लगे हुए इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, क्या उनको वह नहीं बेची जा रही है? मान्यवर, इसमें करोड़ों रुपये का घपला हो रहा है जबकि ये कांग्रेस राज्यों की बात करते हैं। आज तक पूर्वांचल में जितना भी विकास का कार्य हुआ, जितने भी ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please conclude.

...(*Interruptions*)

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय : वे सारे के सारे कांग्रेस सरकार की देन है। उसके बाद उत्तर प्रदेश को सिर्फ लूटा गया। वहां आज राजनीति के नाम पर व्यवसाय हो रहा है। ...(व्यवधान) राजनीति का व्यवसायीकरण कर दिया गया है। ...(व्यवधान) लोकतंत्र की मर्यादा का हनन किया जा रहा है। ...(व्यवधान)

जब सदन में ...(व्यवधान) की बात करते हैं, तो हमें शर्म आती है। ...(व्यवधान) यह कैसी नैतिकता की बात करते हैं, कौन सी राजनीति की बात करते हैं? ...(व्यवधान) जिन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा का हनन कर दिया हो ...(व्यवधान) राजनीति का व्यवसायीकरण कर दिया गया हो, उनके मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब श्री पाण्डेय जी की कोई भी बात रिकार्ड में नहीं जायेगी।

...(व्यवधान)*

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): सभापति महोदय, मैं राजकुमारी रत्ना सिंह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने सदन में पर्वांचल के राज्यों पर ध्यान दिलाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं, बहुत ही पिछड़ा हुआ है। उसका सबसे कारण है कि उत्तर प्रदेश के अन्य भागों पर विशेष ध्यान दिया गया, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके लिए मेरी स्पष्ट राय है कि केन्द्र मे कांग्रेस की सरकार अर्से से रही है और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार रही है। आज हमारे तमाम साथी बड़ा शोर मचा रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पूर्वांचल पैकेज की मांग करने के लिए हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, राजनीति करने के लिए नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे पर दोषारोपण करना, एक दूसरे पर लांछन लगाना, आपको क्यों खराब लग रहा है? जब यह कहा जा रहा है कि आपकी सरकार आजादी के बाद रही है, आप जिम्मेदार हैं, तो आप क्यों नहीं सुन रहे हैं? यह बात सुनना चाहिए।...(व्यवधान) हम स्पेशल पैकेज की मांग करने के लिए खड़े हुए हैं। ...(व्यवधान) आपकी सरकार रही है और आप राजनीति कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Silence, please.

...(*Interruptions*)

श्री तूफानी सरोज : आप सुनिये, सहनशक्ति रखिये। ...(व्यवधान) सच्चाई पर विचार कीजिए। अगर पूर्वांचल पिछड़ा है ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Rashid *ji*, please sit down.

...(*Interruptions*)

श्री तूफानी सरोज : पूर्वांचल के लिए स्पेशल पैकेज की मांग कीजिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप सब बैठ जाइये।

â€¦(व्यवधान)

श्री तूफानी सरोज : महोदय, पूर्वांचल में बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, बनारस आदि चार-पांच जिले ऐसे हैं जो तीन वर्षों से लगातार सूखे से प्रभावित हैं। वहां बरसात नहीं हो रही है जिसकी वजह से भूगर्भ जल का स्तर नीचे चला जा रहा है। वहां लोग पीने के पानी के लिए तरस रह हैं।...(व्यवधान) पिछले दिनों हमने देखा था, केन्द्र सरकार का एक आंकड़ा आया था कि बरसात के पानी को स्टोर करने के लिए इन्होंने 75,000 करोड़ रूपए की व्यवस्था की थी, उस पैसे से बरसात का पानी रोकने के लिए जो सेट बनाया गया था, पता नहीं उससे 75,000 लीटर पानी रूका या नहीं, यह केन्द्र सरकार जाने, उसकी नीयत जाने। रेनफेड वाटर शेड की स्थापना की गयी थी, लेकिन मैंने पूर्वांचल में नहीं देखा कि कहीं भी जल संचयन की ऐसी व्यवस्था की गयी हो। सरकार क्या करती है?...(व्यवधान) आप ही बोल लीजिए। आप ही बता दीजिए।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : सरोज जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री जे.एम.आरुन रशीद (थेनी): सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बारे में बोल रहे हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसमें तमिलनाडु की बात कहां से आई है। आप बैठिए।

â€¦(व्यवधान)

श्री तूफानी सरोज : इंडस्ट्री प्वाइंट ऑफ व्यु से देखा जाए तो पूरे पूर्वांचल में सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली के अलावा केन्द्र सरकार को कोई दूसरा जिला दिखाई नहीं देता है। जब भी केन्द्र सरकार में बात उठती आती है, उत्तर प्रदेश का ध्यान आता है कि वहां इंडस्ट्री लगाई जाए तो सिर्फ रायबरेली, अमेठी ध्यान आता है, अन्य जिलों का ध्यान नहीं आता है। पूर्वांचल में चारों ओर भुखमरी है, कोई उद्योग-धंधे नहीं हैं। बिजली की हालत यह है कि आज भी गांव के बच्चे यह नहीं बता पा रहे हैं कितने दिन पहले मैंने बिजली की रोशनी में पढ़ाई की है। कब बिजली आती है, कब चली जाती है, कुछ पता नहीं चलता है। इस समय पांच, छः, सात, दस घण्टे का रेशियो बनाया गया है। दस घण्टे रेगुलर बिजली नहीं मिलती है, पांच-छः घण्टे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती है। मुंबई में उत्तर प्रदेश के लोगों की जो आबादी है, उसमें 50 प्रतिशत हमारे गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, गोण्डा, बहराइच, बनारस और देवरिया के लोग हैं। अगर पूर्वांचल में बिजली की समुचित व्यवस्था कर दी जाए, तो ये जो लोग मुंबई में जाकर लाठी-डण्डे खाते हैं, गालियां सुनते हैं, दोयम दर्जे के नागरिक माने जाते हैं, वे कतई मुंबई न जाएं, वे अपने घर पर ही बिजली के माध्यम से छोटे-छोटे उद्योग लगाकर काम कर सकते हैं। पूर्वांचल के लोग बहुत मेहनती हैं। जब वे जाकर मुंबई में पैसा कमा सकते हैं, तो उनको अगर बिजली की व्यवस्था दे दी जाए, बिजली की समस्या हल हो जाए तो किसान इतने मजबूत हैं कि काश्तकारी करके अपना जीवनयापन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को भी किसानों की चिंता नहीं है। लखनऊ की राजधानी पत्थरदिल हो गयी है, तो वे जिन्दादिल की क्या बात सोचें कि पूर्वांचल के किसानों पर क्या बीत रही है, बिजली मिल रही है या नहीं, पानी मिल रहा है या नहीं, उनके खेतों की सिंचाई हो रही है या नहीं? उत्तर प्रदेश सरकार ने इन चीजों को एकदम से छोड़ ही दिया है। लेकिन केन्द्र सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि आप जिन्दादिल हैं। पूर्वांचल के लोगों का सम्मान कीजिए। वहां के लिए कम से कम 50,000 करोड़ रूपए का पैकेज देने की मैं मांग करता हूं।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री कमल किशोर 'कमांडो' (बहराइच) : महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं राजकुमारी रत्ना सिंह जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि कम से कम पूर्वांचल के विकास के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की है। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्य सभी क्षेत्रों से ज्यादा आबादी है। यहां पर कोई भी किसी प्रकार का उद्योग धंधा नहीं है। इसका मुख्य कारण यह रहा है कि पिछले 20 सालों से वहां कभी समाजवादी पार्टी और कभी बसपा की सरकारें रही हैं। यही कारण है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज इतनी गरीबी है और बेरोजगारी की समस्या है।

इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुपोषण की भारी समस्या है। इस क्षेत्र में कम से कम 22 प्रतिशत लोग दलित हैं। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि सपा और बसपा की सरकारें जो पिछले 20 सालों से उत्तर प्रदेश में रही हैं, इनके कार्यकाल में एक भी उद्योग लगाया हो, तो मुझे बताएं, सदन में मेरे इतने साथी बैठे हुए हैं, वह मुझे बता दें। वहां पर बिजली उत्पादन का कोई प्लांट इनके कार्यकाल में नहीं लगा, जिस वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पूरे प्रदेश में बिजली की गम्भीर समस्या है। वहां पर पहले जो विकास कार्य हुए, वे कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय ही हुए, उसके बाद कोई विकास का काम नहीं हुआ। इस बात को मानना पड़ेगा कि अगर वहां के लोग कांग्रेस पार्टी की लाइन पर आप चलेंगे तो पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है।

आज हमारे प्रदेश में दलितों की बहुत बात की जाती है। मैं खुद दलित हूं और जानता हूं कि इन लोगों के दलों की सरकारों ने दलितों के उत्थान के लिए क्या काम किए हैं, कुछ भी नहीं किए। अगर वहां पर दलितों के लिए कोई काम हुए हैं, तो वे कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में हुए हैं। मैं दलित का बेटा होने की हैसियत से यह बात बता रहा हूं।

जब हमारे राज्य में राहुल गांधी जी का दौरा होता है तो उसका वहां विरोध किया जाता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जिस दल की वहां सरकार है, क्या उसके मुखिया ने लखनऊ के अलावा राज्य के और किसी हिस्से में दौरा किया है। वहां की सरकार को तो सिर्फ लखनऊ में पत्थर लगाने से ही फुर्सत नहीं है। अगर किसी गरीब के घर पर पत्थर लगाएं तो उसका भी भला हो जाए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि केवल मूर्तियां लगाने से ही पूर्वांचल का विकास नहीं होगा। पूर्वी प्रदेश का विकास तभी सम्भव है, जब वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जिसके पीछे सारी जनता होगी और वह वहां के लोगों का विकास करेगी। आज हम लोग यहां लोक सभा में बैठे हैं, यह किसकी देन है। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है तो बाबा साहेब अम्बेडकर कहां से आए थे, उन्हें कौन लाया था, किसने उन्हें अधिकार दिया था, कांग्रेस पार्टी ने अधिकार दिया था।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : पांडेय जी आप बैठ जाएं। जब एक माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं तो उन्हें बीच में इस तरह से टोकना सही नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप बोल चुके हैं, अब आपकी बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान) *

श्री कमल किशोर 'कमांडो' : बाबा साहेब अम्बेडकर में अपनी योग्यता थी इसलिए उन्हें इतना सम्मान मिला।...(व्यवधान) आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिर्फ धन इकट्ठा करने के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा है।...(व्यवधान) वहां कोई विकास का काम हो रहा हो तो मुझे बता दें।...(व्यवधान)

सभापति महोदय: पांडेय जी, जगदम्बिका जी आप सब बैठ जाएं। यह कोई तरीका नहीं है इस तरह से बीच-बीच में आप टोका-टाकी करें।

श्री कमल किशोर 'कमांडो' : सभापति महोदय, जितना इन्हें अधिकार है बोलने का, उतना ही मुझे भी है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप लोग बैठ जाएं। आप अपनी बात कह चुके हैं। अब आपकी कोई बात रिकार्ड में नहीं जा रही है।

श्री कमल किशोर 'कमांडो' : आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की सड़कों की हालत देखें, बहुत दयनीय स्थिति है। आज पूर्वांचल में जितना भ्रष्टाचार हो रहा है, यह उसका जीता जागता उदाहरण है। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा। मैं रत्ना सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को सदन में पेश किया, जिसकी वजह से हम पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्याओं, उसके विकास के बारे में और वहां के लिए स्पेशल पैकेज देने के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

जब राहुल गांधी जी ने बुंदलेखंड के लिए स्पेशल पैकेज देने की मांग की थी, तो वहां की सरकार ने क्या-क्या नाटक किया था, इसे सब अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि विकास के कामों में इस तरह से ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज वहां के किसान आत्महत्या कर रहे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने वहां पर दौरा करके उन लोगों की हिम्मत बढ़ाई है, मैं यह कहना चाहता हूं कि सारे प्रदेश की जनता और हम सब उनके साथ हैं। आप गांवों में जाकर देखिए कि वहां क्या हालत है। वहां की सरकार को तो सिर्फ लखनऊ ही दिखाई देता है। मैं बहराइच से आता हूं और बहराइच से गोरखपुर मेरा सप्ताह में निश्चित रूप से एक बार आना-जाना होता है। इसलिए मैं जानता हूं कि वहां देहातों में किस कद्र गरीबी है और किस तरह गरीब लोग मर रहे हैं। अगर उन गरीबों की कोई बात सुनता है, उनके विकास की बात करता है तो इसमें गलत क्या है। अगर कोई गरीबों के लिए और उनके विकास के लिए काम करेगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर): सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, you can speak from your seat. Otherwise, at least you take permission from the Chair और आप अपनी बात पांच मिनट में समाप्त कीजिएगा।

श्री विजय बहादुर सिंह : आपने मुझे बोलने का पांच मिनट का समय दिया है। मैं वायदा करता हूं कि मैं चार मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, लेकिन उसमें किसी अन्य माननीय सदस्य का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair and do not look at them.

श्री विजय बहादुर सिंह : राजकुमारी रत्ना जी ने जो बिल पेश किया है, यह बहुत अच्छा बिल है। पुराण में भी लिखा है कि जब-जब यज्ञ होता है, तो राक्षस आते हैं।...(व्यवधान) मैं डिबेट का लेवल उठाना चाहता हूं। मैं आपको एक वाक्य सुनाना चाहता हूं, जब इंगलैंड में लार्ड डेनिंग चीफ जस्टिस थे। यह एक्ट में लिखा है। एक लड़के ने अपने माता-पिता का मर्डर कर दिया। जब उस पर मुकदमा चला, तो बैरिस्टर्स ने बहस की कि इसे माफ कर दिया जाए, क्योंकि यह अनाथ हो गया है।

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, the time extended for this Resolution is over. If the House agrees, the time for this Resolution may be extended by another one hour.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: The time for this Resolution is extended by one hour. There are two more Members to speak. Then the hon. Minister will reply and thereafter the mover of the Resolution will also reply. Then we will take up Dr. Raghuvansh Prasad Singh's Resolution. Please confine your speech to five minutes.

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदय, मुझे इस पर आपत्ति है, मैंने इस बारे में लिख कर दिया है। प्राइवेट मेम्बर बिल के लिए नियमावली में है कि जो समय निर्धारित है, उस समय सीमा में निजी विधेयक और संकल्प को पूरा करना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: If the House agrees, the time can be extended not only once, but more than once. You are a very senior Member, please sit down.

श्री विजय बहादुर सिंह : जब मुकदमा हाउस आफ लार्ड्स में गया, तो बैरिस्टर ने कहा कि इसे माफ कर दीजिए, क्योंकि यह लड़का अनाथ हो गया है। लार्ड डेनिंग ने कहा कि प्रश्न यह नहीं है कि इसे माफ कर दिया जाए, प्रश्न यह है कि इसे अनाथ किसने किया। He himself was the author of his orphanage by

murdering his father and mother. आप कह रहे हैं कि यह अनाथ हो गया है, इसे माफ कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का यही हाल हुआ है। मैं बताता हूं कि कैसे पूर्वांचल का यह हाल हुआ है।

17.00 hrs.

आप सुनिए कैसे हुआ? 61 साल के सफरनामे में 43 साल कांग्रेस ने राज किया। सबसे पहले पंडित जवाहर लाल नेहरु प्रधानमंत्री हुए फिर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव जी, चन्द्रशेखर जी और विश्वनाथ प्रताप जी हुए। यह लगातार चल रहा है और आज जैसा ये कह रहे हैं कि भूखे कगार में हैं You are like the child about whom I mentioned just now. You have orphaned yourself. ...(*Interruptions*) आप बात को समझ नहीं रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसका कारण है कि 45 साल तक इन्होंने हमारी जनता को भ्रम में रखा। ये कहते थे हमने आजादी ली और सिर्फ दो बैल जोड़ी और हाथ में वोट लेकर चले जाते थे। इन्होंने विकास का काम नहीं किया बल्कि विनाश का काम किया। आज आप पैकेज मांग रहे हैं? मैं आपके सामने यह बात कहना चाहता हूं जैसे गोरखपुर की बात है, इतना बड़ा फर्टीलाजर चांद छाप यूरिया था, इनके ही राज में, जब कांग्रेस का राज था, इसमें ताला लग गया। तब हम उनके वकील थे और आज 5,000 वर्कर दस साल से बेकार हैं। इनमें से 83 वर्कर्स ने आत्महत्या कर ली लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप आज पैकेज मांग रहे हैं? मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं आज आप देखें कि महंगाई हो रही है और 90 रुपए किलो दाल बिक रही है। मैं वकालत करता था लेकिन मेरा बेस एग्रीकल्चर है। किसान ने अपनी दाल 18-20 रुपए बेची और 70 रुपए का डिफरेंस अड़तिया, ट्रंसपोर्टर या बंबई और कोलकाता के बिजनेस मैन का है। इसका कौन जिम्मेदार कौन हैं? शुगर इंडस्ट्री का जो हाल हुआ है, मैं उसे बताना नहीं चाहता हूं। अब आप इनकी होशियारी देखिए कि एकाएक डॉ. भीमराव अम्बेडकर से मोह हो गया। सब कुछ लुटा कर होश में आए तो क्या किया। आप उन्हें माला पहना रहे हैं।...(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Only the speech of Shri Vijay Bahadur Singh will go on record and nothing else will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं चेयर के प्रति आभारी हूं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर जब इलैक्शन लड़े तो कांग्रेस ने एड़ी और चोटी लगाकर उनके प्राइवेट सैक्रेट्री को लड़ाकर हरा दिया। जब विश्वनाथ सिंह प्रधानमंत्री थे...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You suggest measures to improve the area.

श्री विजय बहादुर सिंह : अच्छा गाने वाला अनाप शनाप गाना नहीं गाता है, लाईन नहीं बताता। हम कव्वाली नहीं कर रहे हैं। अगर नेता सदन प्रणब मुखर्जी यहां होते तो कांग्रेस के एमपीज को डिसिपलिन बताते, अनुशासन बताते। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude your speech.

श्री विजय बहादुर सिंह : आप सुन लीजिए। चूंकि बसपा सरकार है इसलिए आप उन्हें परेशान करेंगे। यहां विदेश मंत्री बैठे हैं। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Why are you looking at them? You address the Chair.

श्री विजय बहादुर सिंह : आप सुनिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं कि नेशनल हाईवे 76 और 86 मिर्जापुर पूर्वांचल से होकर इलाहाबाद को टच करके चित्रकूट से आता है। यह हाई वे यूपी, झांसी से क्रास करके जहां से उत्तर प्रदेश में आता है वहां पांच साल से उसका रिपेयर नहीं हुआ है। हमने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि नेशनल गड्ढे को नेशनल मान्यूमेंट बना दीजिए और कहिए यह गड्ढा नेशनल हाईवे का है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Please conclude now. Hon. Member Shri Sanjay Nirupam to speak now.

श्री विजय बहादुर सिंह : आप दूसरी बात सुनिये, आप बहुत कहते हैं कि गरीबों के मसीहा हैं। जब मैं अपनी कांस्टीटुंसी में गया तो देखा कि बीपीएल की सूची में सिर्फ 70 परसैन्ट की अभी कमी है, 20 परसैन्ट का नाम है और 70 परसैन्ट बीपीएल वाले छूट गये। आप इन्हें क्यों नहीं बढ़ाते? आप चाहते हैं कि पैसा, रूपया बांट करके, आप इन्हें दो हजार करोड़ नहीं, पचास हजार करोड़ का पैकेज दे दीजिए। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं संजय निरुपम को बुला चुका हूं। Hon. Member Shri Sanjay Nirupam will speak now. Please sit down.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Shri Vijay Bahadur Singh, you conclude now. I have called him.

SHRI VIJAY BAHADUR SINGH : Sir, I am concluding my speech.

Hon. Chairman, I have been requesting and begging of you that if there is an interruption, then I must be given time for the time that has been eaten in interruptions and which is not ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: After reducing the time taken in interruptions, you have spoken for more than six minutes. Please sit down now.

...(*Interruptions*)

श्री विजय बहादुर सिंह : ये â€¦.* बच्चे हैं।

MR. CHAIRMAN: This will not go on record. Please sit down now.

(Interruptions) â€¦

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं लास्ट लाइन कह रहा हूं। आप सुनिये, यह आपके फायदे की बात है। मैं कह रहा हूं कि बीपीएल कार्ड की जो संख्या है, अगर आप बड़े भारी धन्नासेठ हैं तो बीपीएल कार्ड की संख्या क्यों नहीं बढ़ाते? आप चाहे पचास हजार करोड़ या एक लाख करोड़ का पैकेज दे दीजिए, लेकिन अगर आपकी मानसिकता सिर्फ वोट लेने की है तो यह गलत है।

MR. CHAIRMAN: You have made your point. Please conclude.

श्री विजय बहादुर सिंह : बीपीएल की इनकी जो डिमांड है, उसे मैं सपोर्ट करता हूं और पूर्वांचल के लिए जितनी जरूरत हो, उससे ज्यादा उन्हें दीजिए, इसमें हमें कोई गिला नहीं है। लेकिन बहन जी ने 80 हजार करोड़ मांगा और आपने अस्सी रुपये भी नहीं दिये। यह कौन सौ मजाक है?

MR. CHAIRMAN: Shri Vijay Bahadur Singh, please sit down. I have called him.

श्री विजय बहादुर सिंह : मैं अंत में कहना चाहता हूं ... (Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: This will not go on record.

It is required not only on this side, but it is required on every side.

Shri Sanjay Nirupam.

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने की अनुमति दी। मैं माननीय सदस्या, राजकुमार रत्ना सिंह का बहुत आभारी

17.08 hrs. (Dr. M. Thambidurai *in the Chair*)

हूं और उनका अभिनंदन करता हूं कि वह एक महत्वपूर्ण विषय प्राइवेट मैम्बर रिजोल्यूशन के जरिये इस सदन में लाई हैं। पूर्वांचल का विकास नहीं हुआ, पूर्वांचल पिछड़ा है या विकास की गति में पीछे रह गया, इसका रिफ्लैक्शन अगर सबसे ज्यादा कहीं दीखता है तो मुम्बई में दीखता है। पूर्वांचल के अलग-अलग जिलों के लोग मुम्बई शहर में रह रहे हैं। मैं यह बार-बार कहता हूं और आज एक बार फिर से इस सदन में कहता हूं कि जो पूर्वांचल से गये हुए लोग मुम्बई में हैं, वे भोजपुरी भाषी लोग हैं, पूरे मुम्बई में हर सिग्नल पर, हर भाषा में भीख मांगने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन भोजपुरी भाषा में भीख मांगने वाला कोई व्यक्ति नहीं दीखता और यह इस बात का सबूत है कि पूर्वांचल से गया हुआ जो हमारा वर्ग है, वह मेहनतकश मजदूर है। वह मेहनत करता है और मेहनत की दो रोटियां कमाता है और वह न सिर्फ मुम्बई में अपना घर बसाता है, बल्कि जौनपुर, गाजीपुर, बलिया आदि में भी एक घर बना लेता है। जो ऐसा मेहनतकश मजदूर वर्ग है, उसका गांव, उसका क्षेत्र, उसका प्रांत विकास के लिए तरस रहा है, यही दर्द लेकर आज राजकुमारी रत्ना सिंह जी इस सदन में प्रस्ताव लेकर आई हैं और मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का एक अभिन्न हिस्सा है। पूर्वांचल से सौ किलोमीटर दूर मेरा गांव है। हम जितना पटना को जानते हैं, उससे ज्यादा काशी, बनारस को जानते हैं। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो तीन महत्वपूर्ण तीर्थ काशी, मथुरा और अयोध्या हैं, इनमें से दो महत्वपूर्ण तीर्थ पूर्वांचल में पड़ते हैं। एक बनारस में और दूसरा अयोध्या में पड़ता है। यदि पूरे पूर्वांचल को अगर ऐतिहासिक, पारम्परिक और धार्मिक दृष्टि से देखें तो इस देश का सारनाथ, बुद्धिस्ट सैंटर भी वहां है। पूरे देश में पूर्वांचल का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पूर्वांचल ने हमारे देश को कितने प्रधान मंत्री दिये हैं। अगर हम पंडित जवाहर लाल नेहरू जी से शुरू करें तो पंडित जवाहर लाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा जी, राजीव जी, वी.पी. सिंह जी, हमारे चन्द्रशेखर जी बलिया के थे, पूरे देश की आजादी के आन्दोलन का बिगुल बजाने वाले स्वर्गीय मंगल पांडे, अमर शहीद मंगल पांडे भी बलिया के थे। मंगल पांडे, चितू पांडे, जिसका इस तरह का एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा हो, वह पूरा क्षेत्र आज पिछड़ गया है, मैं इस बात के ऊपर दुख व्यक्त करने के लिए में आपके सामने सदन में उपस्थित हुआ हूं। मैं चाहूंगा कि पूर्वांचल का विकास करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक पैकेज आना चाहिए। भदोही जैसा एक छोटा सा जिला पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में सबसे ज्यादा कारपेट का उत्पादन करता है। वहां से कारपेट का एक्सपोर्ट होता है। भदोही में एसईजेड़ लाने का प्रस्ताव था, मुझे पता नहीं कि अब उस प्रस्ताव की क्या स्थिति है? एक-दो साल पहले मैं बनारस से भदोही घूम रहा था तो मुझे बताया गया कि यह-यह एरिया एक्वायर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि विकास के दृष्टिकोण से भदोही का विकास बहुत आवश्यक है। इलाहाबाद का विकास बहुत आवश्यक है। इलाहाबाद एक समय इस देश की साहित्यिक राजधानी मानी जाती थी। सबसे ज्यादा विद्वान लोग वहां पर थे, सबसे ज्यादा लिखने-पढ़ने का काम वहां पर होता था। बड़े-बड़े साहित्यकार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से शुरू करें तो अमरकांत जी तक वहीं रहते थे।...(व्यवधान) सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पूरी जिन्दगी इलाहाबाद में रहे हैं, मैं खुद उनका घर देखकर आया हूं। मेरा कहने का आशय यह है कि जिस पूर्वांचल का इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है, जिसकी पृष्ठभूमि इतनी अच्छी रही है, वह पूर्वांचल आज पीछे छूट गया है और उस पूर्वांचल को आगे लाना चाहिए। काशी, बनारस धार्मिक टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेंटर है, हम सब कम से कम साल में दो बार वहां चले जाते हैं, हम भी बनारस चले जाते हैं। ऐसे बनारस का डेवलपमेंट सही मायने में नहीं हो रहा है। इसके लिए कहीं न कहीं एक पूरी ताकत लगनी चाहिए, एक सोच लगनी चाहिए, एक विजन आना चाहिए। दुर्भाग्यवश आज पूर्वांचल में यह हो रहा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : Hon. Member, please wind-up your speech.

...(*Interruptions*)

श्री संजय निरुपम : महोदय, मैं एक-दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। आज दुर्भाग्यवश उत्तर प्रदेश में मूर्तियां बनायी जा रही हैं। ...(व्यवधान) आपको ऐसा सुनकर बहुत तकलीफ होती है। पूर्वांचल के लोग पूछते हैं तो बोलते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में 14 हजार करोड़ रूपये खर्च करके मूर्तियां पर मूर्तियां बनायी जा रही हैं। मुझे लगता है कि सरकार के द्वारा सही दिशा में काम करने का काम नहीं हो रहा है। ...(व्यवधान) दारा सिंह जी, आपके मऊ और आजमगढ़ के लोग बड़े पैमाने पर हमारे शहर में रहते हैं और हम बड़े आदर के साथ उनके साथ मिल-जुलकर काम करते हैं।

महोदय, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि पूरे मुंबई में टैक्सी चलाने वाले लोग प्रतापगढ़ के हैं, जहां की रत्ना जी हैं। पूरे मुंबई में दूध बेचने वाले लोग जौनपुर, बनारस के हैं, पूरे मुंबई में सब्जी और फल बेचने वाले लोग गोरखपुर, आजमगढ़ के हैं। पूरे मुंबई से पूर्वांचल का एक अभिन्न रिश्ता है और उस रिश्ते के तकाजे पर मैं आज सदन में खड़े होकर कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का थोड़ा सा ध्यान अब पूर्वांचल के विकास के लिए लगना चाहिए।

MR. CHAIRMAN: Dr. Raghuvansh Prasad Singh, you can start speaking.

...(*Interruptions*)

श्री संजय निरुपम : महोदय, मुझे यह बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि जब प्रतापगढ़ के आश्रम में अभी भगदड़ मची और सैंकड़ों की संख्या में लोग मर गये, सौ के करीब लोग मर गये, तब आपकी मुख्यमंत्री जी वहां नहीं गयीं, लेकिन हमारे नौजवान नेता श्री राहुल गांधी जी दिल्ली से स्पेशली वहां गये और लोगों से मिलकर आये, उनको सहूलियतें दीं।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री...(व्यवधान) ने पिछले तीन साल में कितनी बार पूर्वांचल का दौरा किया है?...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Please do not convert the Parliament into UP Assembly. Please, I request you not to convert the Parliament into UP Assembly.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: You had raised the point, and I do not want this kind of thing.

...(*Interruptions*)

श्री संजय निरुपम : महोदय, यह अपने आप मे सोचने का विषय है।...(व्यवधान) मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि पूर्वांचल कहीं न कहीं राज्य सरकार की उपेक्षा का शिकार हुआ है। केंद्र सरकार की तरफ से तो पैकेज आना ही चाहिए, लेकिन राज्य सरकार को भी विशेष तौर से पूर्वांचल के विकास के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): महोदय, इस संकल्प के लिए राजकुमारी रत्ना सिंह जी को धन्यवाद। सरकार की नीति रीजनल डिस्पैरिटी दूर करने की है, लेकिन यह पिक एंड चूज करके नहीं होना चाहिए। इन्होंने बुन्देलखंड को जो पैकेज दिया, यह ठीक किया, वहां रीजनल डिस्पैरिटी है, ज्यादा पिछड़ापन है, गरीबी है, सुखाड़ की मार है, उसके लिए पैकेज दिया है। उसी के पास में पूर्वांचल की भी ऐसी ही स्थिति है। हमें इसके बारे में बोलना नहीं था क्योंकि हम लोभ में थे कि हम अपने संकल्प पर बहस करेंगे, लेकिन मूव के अलावा उस पर आज गुंजाइश नहीं है तो मुझसे बिना बोले नहीं रहा नहीं गया।

यह राजनीतिक बहस जो हुई है क्यों, कहाँ, कैसे, इससे जनता और पूर्वांचल का हित होने वाला है। विषय है कि बुंदेलखंड का पैकेज आपने दिया तो पूर्वांचल को क्यों नहीं देंगे? यह हम सरकार से जानना चाहते हैं। इसी में यह बात खुल जाएगी कि जितने लोगों ने समर्थन किया है और बोल रहे हैं कि वाह-वाह, मिलना चाहिए, तुंत ही अभी पीछे हटेंगे। ...(व्यवधान) नहीं हटेंगे? मैं अभी यह साफ करना चाहता हूँ कि पूर्वांचल को पैकेज देने से कोई शक्ति रोक नहीं पाएगी। सब लोगों का समर्थन है, संपूर्ण हाउस का समर्थन है। इन लोगों ने भी कुछ कहा-सुनी की है, आपके चलते इन सबके चलते, लेकिन क्या आप पूर्वांचल के पैकेज के समर्थन में हैं? संपूर्ण

हाउस का समर्थन है। आप अभी सरकार की तरफ से देखेंगे मगर मैं सरकार को खबरदार करना चाहता हूँ अगर उन्होंने आग्रह किया कि इस संकल्प को वापस लीजिए। नहीं तो वोट होगा और हम इसको पास कराएँगे। इसीलिए हम खड़े हुए हैं। नहीं तो अभी यह बात खुल जाएगी कि वोट आप किधर देंगे। सरकार की पालिसी है कि रीजनल डिसपैरिटी दूर की जाएगी। जब बुंदेलखंड के पिछड़ेपन पर आपने पैकेज दिया है तो पूर्वांचल की आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं? यदि ऐसा होगा तो पूर्वांचल को राज्य बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि रीजनल डिसपैरिटी के चलते ही देश की अखंडता को खतरा है। आज जो छोटे-छोटे प्रदेशों की मांग होती है, रीजनल डिसपैरिटी के कारण ही होती है। देश में अनेक समस्याएँ हैं। उसके साथ-साथ क्षेत्रीय विषमता भी है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश के अंदर क्षेत्रीय विषमता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आगे है, पूर्वी उत्तर प्रदेश पीछे है, बुंदेलखंड और पीछे है। इसीलिए पैकेज की मांग का औचित्य है। आपने उसी प्रदेश में एक पिछड़े इलाके बुंदेलखंड को पैकेज दिया है, तो यहाँ पैकेज नहीं देने का काई कारण नहीं है। इसलिए श्री नारायणस्वामी जी को अभी बोलना पड़ेगा कि आप पैकेज दे रहे हैं या नहीं, नहीं तो वोट के लिए आप तैयार हो जाइए। उधर का एक भी आदमी आपको सपोर्ट नहीं करेगा कि पैकेज नहीं मिलना चाहिए, इस पर संपूर्ण हाउस का समर्थन है। इससे रीजनल डिसपैरिटी दूर होगी और पूर्वांचल के बारे में जो वर्णन किया, लोगों ने उसका इतिहास, भूगोल, संस्कृति की राजधानी आदि सब के बारे में कहा, उस पर बहुत बहस का समय नहीं है। इसलिए मैं समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूँ कि अभी ऐलान होना चाहिए कि वहाँ के लिए पैकेज मिलेगा। कितना कहां और कैसे पैकेज मिलेगा, यह मौका मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ लेकिन अभी आपको बोलना पड़ेगा कि पूर्वांचल को बुंदेलखंड की तरह पैकेज मिलना है और सरकार की तरफ से भेदभाव नहीं होता है, पिक एंड चूज़ नहीं होता है, गैर-बराबरी नहीं होती है, यह आपको सोचना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूँ। मैं उत्तर की प्रतीक्षा में हूँ कि सरकार की तरफ से पॉजिटिव उत्तर आ रहा है या नहीं। सरकार यह न कहे कि हमने यह किया, वह किया इसलिए इस संकल्प को वापस कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का पूरा समर्थन करता हूँ।

MR. CHAIRMAN : The Minister wants to reply today itself. Therefore, please be brief, Shri P.L. Punia. Today, we want to complete this. Please try to be brief.

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस संकल्प पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बधाई देना चाहता हूँ बहन राजकुमारी रत्ना सिंह जी को कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को संकल्प के रूप में यहाँ रखा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की चर्चा हुई है और सभी दलों ने इसका समर्थन किया है, यह वास्तव में महत्वपूर्ण विषय है, समय की आवश्यकता है, पूर्वांचल के विकास के लिए विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए, पूर्वांचल के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। आप जानते हैं कि कानपुर से फतेहपुर से आगे नेपाल बार्डर तक पूर्वांचल है। उसके बाद बिहार में भी कुछ क्षेत्र है जिसको पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। वह पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। वहाँ सबसे ज्यादा गरीबी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है मगर ज़मीन सबसे ज्यादा उपजाऊ है। यह गौतम बुद्ध की भूमि जहाँ कुशीनगर है, श्रावस्ती है, लुम्बिनी है, सब स्थान वहाँ हैं, पूरे विश्व से लोग वहाँ आते हैं, जापान से लोग आते हैं, कोरिया से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं, लेकिन इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। बुद्धिस्ट सर्किट के नाम से वहां सड़कें बनीं, लेकिन वे टूट-फूट गई और अब उनका कोई पूछ-हाल नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि यहां की जनसंख्या ज्यादा है। यहां घाघरा, गंगा, राप्ती, गंडक और बूढ़ी गंडक नदियां बहती हैं। हर साल बाढ़ की विभीषिका से करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं। हर साल वे विस्थापित होते हैं, उनकी झोंपड़ी उजड़ती है, हर साल फिर वे बनाते हैं, अगले साल फिर उनकी झोंपड़ी उजड़ती है। विकास कैसे होगा? इस प्रकार से विकास नहीं हो सकता है। हमारा क्षेत्र घाघरा नदी के किनारे पड़ता है, इसलिए हम लोगों ने मांग की थी कि घाघरा नदी के किनारे बांध बनाया जाए। मैं पवन बंसल जी का आभारी हूं कि उन्होंने राज्य सरकार से कहा कि आप इसका जल्दी से जल्दी सर्वे करके, इसका प्रस्ताव गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, पटना के माध्यम से भेजें ताकि उसको बनाया जा सके। लेकिन उसका सर्वे बहुत धीमी गति से हो रहा है। राज्य सरकार को इसमें तीव्रता लानी चाहिए। मैं इसमें कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। उसमें सभी लोग प्रभावित हैं। वहां जगह-जगह रेलवे ओवरब्रिज हैं।

मैंने मांग रखी थी कि देवा रोड़ से बाराबंकी पर रेलवे ओवरब्रिज बनना चाहिए, लेकिन वह लटका हुआ है। उसके लिए राज्य सरकार का एक सर्टिफिकेट चाहिए कि यह पुल बनने के बाद नीचे का फाटक बंद हो जाएगा। लेकिन उसमें पता नहीं क्या कठिनाई है? इन कठिनाइयों को दूर करते हुए यदि विकास का हर काम होता जाए, तो विकास हो जाएगा। आपको याद होगा कि पूर्वांचल निधि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई थी, आज भी वह चल रही है, जिसे शुरूआत की कांग्रेस पार्टी सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया था। कांग्रेस पार्टी ने इस बारे में पहले से सोचा, उन्होंने बुंदेलखंड और पूर्वांचल की निधि अलग से दी थी, ताकि पिछड़े क्षेत्रों का विकास हो सके। मैं आभारी हूं कि बुंदेलखंड के लिए पैकेज मिला और उसके साथ-साथ एक एथारिटी बनाने की बात भी कही गई, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार द्वारा कहा गया कि एथारिटी के लिए हम सहमत नहीं हैं। एथारिटी में क्या कठिनाई है? वास्तव में जो पैसा जा रहा है, वह योजनाओं पर खर्च नहीं हो रहा है। पूर्वांचल में दूसरी ग्रीन रैवोल्यूशन के लिए चार सौ करोड़ रूपये, जिसमें बिहार भी सम्मिलित है, अभी-अभी दिया गया है। तीन हजार करोड़ रूपये 60 हजार विलैंजिस के लिए दिए गए हैं। भारत निर्माण योजना और नरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से पूर्वांचल का विकास हो सकता है, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि राज्य सरकार हर चीज में ...(व्यवधान) â€¦ *करती है। उनको विकास के लिए फुर्सत नहीं है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : You cannot use that word 'corruption'. That word will not go on record.

*(Interruptions) â€¦ **

श्री पन्ना लाल पुनिया : मुख्यमंत्री को अपनी मुर्तियां स्थापित करने की फुर्सत है, बाकी किसी चीज के लिए फुर्सत नहीं है।...(व्यवधान) यदि भ्रष्टाचार की बात हो रही है और यदि भ्रष्टाचार पर यहां चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी?...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: In the beginning itself I had said that please do not convert this Parliament into Uttar Pradesh Assembly.

श्री पन्ना लाल पुनिया : भ्रष्टाचार की बात यदि यहां नहीं होगी तो कहां होगी? मनरेगा ...(व्यवधान) â€¦ *, इस पर चर्चा होनी चाहिए और यहीं पर चर्चा होगी।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You cannot say about a State Assembly. You cannot substantiate it.

...(*Interruptions*)

श्री पन्ना लाल पुनिया : पूर्वांचल के विकास के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, उसमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार भी शामिल हो।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

श्री रमाशंकर राजभर (सलेमपुर): सभापति महोदय, राजकुमारी रत्ना सिंह जी ने जो पूर्वांचल के विकास के लिए संकल्प लाया है, सम्पूर्ण पूर्वांचल का एक-एक सांसद इससे सहमत है, केवल सांसद ही नहीं, बल्कि पूरा सदन इस पर सहमत है। मैं उन विषयों पर जाना नहीं चाहता कि 48 साल तक शासन करने के बाद पूर्वांचल की बात न करने वाले लोग केवल तीन वर्ष के शासन में तमाम आरोप यहां लगा रहे हैं, जब कि यह विषय नहीं है। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि जिन महापुरुषों को आज तक कोई सम्मान नहीं मिला, अगर उत्तर प्रदेश ने सम्मान की प्रक्रिया शुरु की तो उस पर भी बवाल होता है। मैं उधर भी नहीं जाना चाहता, मूल विषयों पर आना चाहता हूं कि पूर्वांचल में एक देवरिया जनपद है, जब कुशीनगर जनपद नहीं बना था तो 13 चीनी मिलें पूरे देश में चीनी भेजती थीं। 13 चीनी मिलों वाला जनपद आज तीन चीनी मिलों के लिए तरस रहा है। फर्टिलाइजर की बात आई। मैं जनपद बलिया से सांसद हूं, 1857 की क्रांति में मंगल पांडेय जी की बलिया की आज हालत यह है कि सम्पूर्ण बिहार का वह बार्डर है, लेकिन आज भी सड़क, बिजली और उद्योग के लिए वह तरस रहा है। कितने प्रधान मंत्री बहुजन समाज पार्टी के हुए हैं, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन जितने भी हुए, वहां से सभी लोगों ने पूरे देश में जोत जगाने का काम किया, लेकिन पूर्वांचल की हालत क्या है, आज मैं कहना चाहता हूं कि बाढ़ और सूखाड़ की चर्चा के साथ-साथ पूर्वांचल की हालत यह है कि इंदिरा आवास योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों का हम आवास बनवाते हैं। आज गरीबों की गांव-गांव में हजारों की संख्या में झोंपड़ियां जल रही हैं और उनका नाम बीपीएल सूची में नहीं है। ये जो झोंपड़ियां जलीं, उसमें उनकी बेटियों की शादी का पैसा जला, उनके बच्चों के भोजन का अनाज जला, उनका अगर बीपीएल सूची में नाम नहीं है तो वह झोंपड़ी नहीं बना सकता। पूर्वांचल के पैकेज के लिए जितना भी सदन सहमत है, मैं भी उसमें बल देते हुए सहमत हूं। पूर्वांचल के लोग पूरे देश में जाकर मुंबई, हरियाणा और पंजाब बना सकते हैं, वही पूर्वांचल के लोग तरस रहे हैं।...(व्यवधान) यह कैसी बात है? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पूर्वांचल के विकास के लिए यह पैकेज जितना अधिक से अधिक हो सके, दें। जब सचमुच में उत्तर प्रदेश की सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है तो हमारे घर के साथी अगर सचमुच में इस पर जवाबदेह हैं और ईमानदार हैं तो पैकेज की घोषणा होनी ही चाहिए।

सभापति महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Chairman, Sir, I am grateful to hon. Members: Rajkumari Ratna Singh; Shri Hukmadeo Narayan Yadav; Shri Shailendra Kumar; Shri Dara Singh Chauhan; Shri Harsh Vardhan; Shri Ramkishun; Shri Jagadambika Pal; Shri Ghanshyam Anuragi; Shri Prasanta Kumar Majumdar; Shri Adhir Chowdhury; Shri Gorakhnath Pandey; Shri Sanjay Nirupam; Dr. Vinay Kumar Pandey; Shri Tufani Saroj; Shri Kamal *alias* Commando Kishor; Dr. Raghuvansh Prasad Singh; Shri B.L. Punia; Shri Ramashankar Rajbhar; and Shri Vijay Bahadur Singh. There are about 17 Members who spoke on this Resolution.

Hon. Member Rajkumari Ratna Singh has given an opportunity to the Members to raise the issues facing Poorvanchal region. In the Resolution she wanted to highlight the socioeconomic backwardness of the Eastern Districts of the State of Uttar Pradesh, also known as Poorvanchal region, and she wanted the House to consider and take immediate steps to formulate and implement a special economic development package for the region on the lines of the package announced by the Government for the Bundelkhand region. This is the Resolution which the hon. Member brought.

When the hon. Members spoke, they have been very particularly mentioning about the backwardness of the region; in the education index, it is backward; health indicators are also not up to the national average; and also the power sector where they need improvement; the road facilities have to be improved; industrial development has to come and it is a thickly populated area where the hon. Member Shri P.L. Punia has highlighted several important areas where they need development. One is about backward area; secondly, he mentioned that the land is fertile; water is available but still we are not able to concentrate more on agricultural production. That point the hon. Member has mentioned.

He has also mentioned about the funds that have been given by the Government – both by the State Government and also by the Central Government – for developing the region but the funds are not sufficient. Therefore, the Government of India has to consider and then, a special package has to be given as it is given to Bundelkhand region. The planning process is being done and after due deliberations, the policy that has been evolved by the National Development Council and thereafter, the Planning Commission calling the officials of the State Government and also the Chief Ministers of various States when the budget is proposed and then submitted for consideration. The Chief Ministers are present in the meeting and thereafter, the budget proposals are cleared, according to the guidelines that have been framed for the whole country. The backward region has been given due care by the Planning Commission at the time of formulating the Budget.

Apart from that, there is a very clear cut policy that apart from the Budget money, the Government of India is giving funds under the Centrally sponsored scheme, that is, additional fund given by the Government of India because there are certain regions where we need more focus. Therefore, the Government of India gives money for those schemes.

As far as Uttar Pradesh is concerned, especially the eastern region where the hon. Member wanted that a special economic package has to be given by the Government of India, the Poorvanchal has got 27 districts which the hon. Members have mentioned and I do not want to go district by district because of paucity of time. But the hon. Members know pretty well and you know that because you have seen the deliberations that has been going on, and the kind of discussions that have been going on, one blaming the other and the other blaming the Members of the Party which is ruling the State. There are some issues which I would like to highlight very clearly. The primary responsibility lies with the State Government for developing the State. The State Government is the authority which prepares the plan, schemes, and projects and send them to the Government of India, either for the Budget or for the Centrally sponsored schemes. It is the duty of the Central Government to supplement the State Government for the purpose of overall development of the State. Therefore, the primary focus lies with the State Government.

I would like to mention only a few figures as to how the Uttar Pradesh Government has been supported by the Government of India. I would not go into the previous periods. Let me start from 2007-08. During the Annual Plan 2007-08, the amount that was given for the Budget was Rs.25,000 crore. In 2008-09, it was Rs.35,000 crore; and in 2009-10, it was Rs.39,000 crore. The total is about 11.42 per cent higher than the Plan outlay of 2008-09. During the 11th Plan, the Government of India has allocated Rs.1,81,094 crore for Uttar Pradesh as against the money allocated during the 10th Plan by the NDA Government.

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी): यह हमारा हिस्सा है, आपने कुछ नहीं दिया।...(व्यवधान)

श्री वी.नारायणसामी : जब आप बोल रहे थे तब मैंने इंटरफियर नहीं किया।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN : If you want to say something, you can speak afterwards. I will permit you. Let the Minister speak. Do not interrupt the Minister now. Let him conclude.

SHRI V. NARAYANASAMY: In the 11 th Plan, the UPA Government has given Rs.1,81,094 crore for the over all development of Uttar Pradesh. It is a plan budget. Then in the Tenth Plan, compared to NDA regime, the Government of India gave Rs.59,708 crore which is 50 per cent more. It is not left with that. I would like to mention here that under the Centrally-sponsored scheme Rs.1,20,264 crore were given. It was only one-third at Rs.35,967 crore in the Tenth Plan under the Centrally-sponsored scheme.

I would like to say under the Centrally-sponsored scheme-wise what is the money provided to Uttar Pradesh because that would highlight how Uttar Pradesh has been taken care of by the Central Government schemes.

श्री दारा सिंह चौहान : आप कहानी बता रहे हैं। आप क्या देने वाले हैं, वह बताइए।...(व्यवधान)

श्री वी.नारायणसामी : आप मेरी बात समाप्त होने के बाद बोलिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूं।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Let the Minister reply.

SHRI V. NARAYANASAMY: Under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, the total amount allocated for one year, namely, 2009-10 was Rs.39,000 crore, out of which Uttar Pradesh alone was given Rs.7384 crore...(*Interruptions*) I am talking from the records. Kindly hear me.

MR. CHAIRMAN: Please listen. You are a leader and if you go on interrupting like this, he will not be able to complete his speech. Let him speak.

SHRI V. NARAYANASAMY: Are you disputing these figures?

MR. CHAIRMAN: Except the Minister's speech, nothing would go on record.

*(Interruptions) â€¦**

MR. CHAIRMAN: He is mentioning the programmes. Please listen to him. He has not finished his speech.

SHRI V. NARAYANASAMY: Kindly hear me. When you were speaking, I did not interrupt you...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: I have not called you people to speak. I have asked the Minister to speak. Nothing would go on record

except the speech of the Minister. You should have patience. You can raise the points afterwards.

*(Interruptions) â€¦ **

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I am telling about the Centrally-sponsored schemes one-by-one. They can speak after my speech.

Under the National Rural Health Mission, Rs.2906 crore were given in 2009-10. Under Indira Awas Yojana, Rs.1056 crore were given. Under the Accelerated Irrigation Benefit Programme, Rs.1752 crore were given. Under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Rs.5500 crore were given. Under Rajiv Gandhi Gramin Vidyuti Karan Yojana, the amount is Rs. 1000 crore. For Integrated Child Development Programme, it is Rs. 844 crore. Under Sarva Siksha Abhyan, the amount is Rs. 3812 crore. Under Jawaharlal Nehru Urban Renewal Mission, it is Rs. 1715 crore. The total figure in 2009-10 is Rs. 30,000 crore which is given to Uttar Pradesh under the Centrally Sponsored Scheme. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please address the Chair, Mr. Minister. What hon. Members are saying will not go on record. Only the hon. Minister's speech will go on record.

*(Interruptions) â€¦ *

श्री वी.नारायणसामी : मेहरबानी करके आप सुनिये। ...(व्यवधान) आप लोगों ने भाषण दिया, तो मैंने शांति से आपको सुना। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Be silent and listen to his reply.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: If every hon. Member interrupts like this, then how can I run the House? So, please cooperate with the Chair. Mr. Minister, address the Chair and no interruptions are allowed.

...(*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: In the XI Plan, the target was about 6.1 per cent growth. But Uttar Pradesh could not reach 5.2 per cent. Agricultural growth has grown from 3.6 per cent to 4 per cent in the previous period. But as far as the tertiary sector, that is, the service sector, it was below national average. It was only 7 per cent but the all India average is between 10 and 10.5 per cent. As far as industrial production in the State is concerned, I would like to mention that it was a revenue surplus State earlier. I mean before 2006 when the surplus was Rs.4900 crore and it declined to Rs.1573 crore in 2009-10. It was a revenue surplus State and the figure got reduced to Rs. 1573 crore. Sir, the hon. Members have been raising a particular point as to why the Government of India is not supporting them. The kind of argument that has been coming is thatâ€¦...(*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Poorvanchal has plenty of water. Even when there was drought in other parts of the country, there was flood in this area. The land there is very fertile. There should be a focus by the State Government for increasing agricultural production there. ...(*Interruptions*)

श्री दारा सिंह चौहान : सभापति महोदय, मंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश के आंकडे बता रहे हैं जबकि यहां पूर्वांचल की बात हो रही है। ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: He is going to explain the situation in Poorvanchal.

...(*Interruptions*)

श्री वी.नारायणसामी : केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को पैसा देगी, पूर्वांचल को अलग से पैसा नहीं देगी। ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश को पैसा देगी, पूर्वांचल को अलग से पैसा नहीं देगी, क्योंकि पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं है। वह उत्तर प्रदेश में ही है।...(व्यवधान) क्या आपको यह नहीं मालूम? ...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Only the Minister's statement will go on record and nothing else will go on record.

(Interruptions) â€¦

MR. CHAIRMAN: After the reply of the Minister, you may raise your points and I will allow you to raise them. Do not interrupt like this.

...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: After the Minister's reply, you can raise these points.

...(*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: I appreciate what they have been doing. In the agriculture sector, the State Government is giving 100 per cent subsidy for sprinkler irrigation. They are giving 100 per cent subsidy for sprinkler irrigation for both Bundelkhand and Poorvanchal regions. I am telling that also.

As far as the power situation is concerned, the State Electricity Board has been divided into three parts. One is for thermal, another is for hydro and the third one is for transmission. But there is only one Chairman. Therefore, we told them that there should be concentration on that. What is the power generation there? The generation capacity is 5,050 mega watt. The State's deficit in peak time is 21 per cent. There is 21 per cent deficit in the State. Now, two power generation units are being promoted. One is for 500 mega watt and another is for about 1,000 mega watt. That plan is under consideration. The State is purchasing power at the rate of Rs. 4.20 per unit. They are purchasing 64 per cent of power from public sector and private sector agencies. When the State Government purchases 64 per cent of power, definitely it is going to be a burden on them.

As far as the rural development is concerned, what kind of employment are they giving to women? It is only eighteen per cent. Under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, only 18 per cent of women are getting employment there, when compared to the national average of 48 per cent. I am giving only the figures. I do not want to go into the details. If I go into the details, then you will be in trouble. ...(*Interruptions*)

In education, the national average is 57 per cent, but in Uttar Pradesh it is only 45 per cent. As far as the health indicators, I do not want to quote the figures.

They were talking about development of Bundelkhand. This region is a dry one. Continuously for three or four years there is no rain and there is no water supply. People are migrating from there to other areas. Therefore, the hon. Prime Minister, hon. UPA Chairperson and on the initiative of hon. Member of Parliament, Shri Rahul Gandhi, a package was given for Bundelkhand region by the Government of India. Now, the Bundelkhand region requires special attention by the Government of India. I went to Bundelkhand region. I went to part of Madhya Pradesh. I was there. ...(*Interruptions*)

I am coming to Poorvanchal. I went to that area. I found that water supply is not there. Roads are not properly maintained. Even for the purpose of getting their day-to-day work done, they are suffering. Therefore, the special package given to Bundelkhand is justified. Therefore, the Government of India, the hon. Prime Minister, hon. UPA Chairperson and Shri Rahul Gandhi took a decision to help the poor people of both the backward regions of Bundelkhand.

MR. CHAIRMAN: What he says is regarding what has been given to Bundelkhand. He is explaining that. Then, he will come to Poorvanchal and other issues. You must listen to that. When the Resolution mentioned about Bundelkhand, therefore, he is saying about Bundelkhand also. Afterwards, he will explain it. You must listen to him.

...(*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: What are the major problems which are there?...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Please do not argue. You are provoking.

...(*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: I entirely agree with the hon. Members....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: When the hon. Minister is speaking, why are you interrupting? When your Minister is speaking, do not argue.

...(*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: It is because industrial development is not there in Poorvanchal area. They want the Poorvanchal issues to be addressed. That is because of poor investment climate. Why? There is plenty of opportunity for developing agro-based industries in Poorvanchal region. The initiative has to be taken by the State Government and the Central Government will help them. But the initiative has to come from the State Government. They are blaming the Central Government....(*Interruptions*)

What has the Central Government to do? The Central Government has to give the money for various schemes. It is for the State Government to implement the schemes....(*Interruptions*)

Now, I come to infrastructure bottlenecks. As I have first said, it is because of the poor investment climate. The infrastructure bottlenecks are there. Thirdly, Uttar Pradesh is a landlocked State. The governance-related issues and policy related issues are there. There are so many factors. My concern is that unless and until the climate is created for industrial development, no industry will come there. For that, a lot of concessions have to be given to the industries which are coming there by the State Government.

As far as Poorvanchal is concerned, a claim has been made. It is educationally backward. Health indicators are not properly there. Apart from that, when compared to Bundelkhand, Poorvanchal has fertile lands. Irrigation facilities are available there. Why do you not increase productivity? The State Government has to take the initiative. I said that they are doing one scheme, the sprinkler irrigation scheme. I support it. The State Government is supporting it. Everybody was telling about roads. Money given by the Government of India under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is Rs.5,500 crore. No other State has got the highest allocation which Uttar Pradesh has got....(*Interruptions*) Uttar Pradesh deserves it. It requires proper implementation by the State Government....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Mr. Minister, please address the Chair.

SHRI V. NARAYANASAMY: If a little focus is given by the State Government to Uttar Pradesh, the Poorvanchal Region will not only satisfy the entire population of Uttar Pradesh in terms of production of food grains but also it can give food grains to the Central kitty. The State Government has to take a lot of steps for increasing agricultural production and productivity, fisheries, etc....(*Interruptions*)

In the Bundelkhand region, other items like dairy farming, live-stock rearing, goattery, poultry, fishery are there. A lot of opportunities are there. The State Government has to focus on them so that a lot of people will get the benefits. There will be employment generation and revenue earning will also be there....(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: No commentary is allowed. Please listen to him. Let him finish. Afterwards, you can speak. I will give an opportunity to you. If at all you want to raise certain issues, I will give you the opportunity. You raise the issue and the Minister will also answer. I am not denying the opportunity to you. Let him finish it.

...(*Interruptions*)

SHRI V. NARAYANASAMY: Poorvanchal region being a thickly-populated area, there is large manpower potential. That larger manpower potential can be utilized for progress, for development and for the purpose of increasing productivity there. But, unfortunately, the focus has to be given on agriculture and industrial development in Poorvanchal, on the tertiary sector also. The initiative has to be there by the State Government.

The Central Government cannot direct the State Government everyday. It is the responsibility of the State Government to utilise the funds given by the Government of India under various schemes and implement the schemes in right earnest. ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN: Nothing will go on record except what the hon. Minister says.

*(Interruptions) â€¦**

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, as far as Eastern Uttar Pradesh is concerned, the hon. Members have mentioned that flood control is one area where focus should be there because the flood situation gets alarming during the monsoon season. The State Government should draw up a plan and it should take all possible steps for controlling the flood situation there.

As far as urban development is concerned, the hon. Members were mentioning about Varanasi. The Government of India is cleaning River Ganga now. They were saying that Ganga water is polluted. For cleaning of River Ganga, when Shri Rajiv Gandhi was the Prime Minister, he gave a package and thereafter the Government of India is concentrating more on cleaning River Ganga. It is not only the responsibility of the Government of India, but it is the responsibility of the State Government also to see that Ganga water is not polluted so that it can be used for drinking water, it can be used for irrigation and also for transport, if possible.

The State Government's focus should be on development of agro industries, industrial development, development of education, employment generation and development of health infrastructure. These are the areas where the State Government has to pay its attention. ...(*Interruptions*)

श्री तूफानी सरोज (मछलीशहर): मंत्री जी ने पूर्वांचल के लिए कुछ नहीं कहा है, इसलिए मैं सदन का वॉक आउट करता हूं।

17.58 hrs.

(Shri Tufani Saroj then left the House)

MR. CHAIRMAN : Hon. Minister, you continue.

SHRI V. NARAYANASAMY: Sir, I will conclude within a minute.

Sir, Poorvanchal is the land of Buddha. It has got very important tourist destinations like Allahabad, Ayodhya and Varanasi. All these religious places are there in the Poorvanchal region. So, roads have to be developed there. If the State Government sends the proposal which is acceptable to the Government of India, we will extend support to them.

Therefore, as the Government of India is giving more and more attention for the development of Uttar Pradesh by providing more funds, I would request the hon. Member to withdraw her Resolution.

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमने मंत्री जी का हमारी मांग के बारे में उत्तर सुना। हमें अब पता लगा है कि हमारी केंद्र की सरकार कितना ज्यादा धन उत्तर प्रदेश को देती है और उत्तर प्रदेश हमारे पूर्वांचल को वह धन नहीं देता है। हमारी राज्य सरकार पूर्वांचल का हक नहीं देती है। हमारी राज्य सरकार को पूरे उत्तर प्रदेश को एक ही प्रकार से देखना चाहिए और हर जिले को उसका हक मिलना चाहिए। आज पूर्वांचल इसलिए पिछड़ा है, क्योंकि बहुत सालों से यहां से कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ है।

18.00 hrs.

पूर्वांचल में कोई जानता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री क्या होता है। सब मुख्यमंत्री वेस्टर्न यूपी के ही रहे हैं। मैं आपके माध्यम से रिजॉल्यूशन् विदड्रॉ करती हूं और एक ही शर्त पर विदड्रॉ करती हूं कि अगली 12वें वित्त में पूर्वांचल की तरफ जब तक दिल्ली से ध्यान नहीं दिया जाएगा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार नहीं आएगी तब तक पूर्वांचल को उसका हक नहीं मिलेगा।

श्री रामकिशुन (चन्दौली): जब बुंदेलखंड को विशेष पैकेज दिया तो पूर्वांचल को विशेष पैकेज देने में क्या प्रॉब्लम है? ...(*Interruptions*)

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

*(Interruptions) â€¦**

MR. CHAIRMAN : Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Rajkumari Ratna Singh be withdrawn?

The Resolution was, by leave, withdrawn.